लखनऊ

शनिवार, 11 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 313

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

इतना काम करिये की काम भी आप का काम देखकर थक जाय।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी बोले- हनुमानगढ़ी में पढ़वाई थी नमाज, जामा मस्जिद में हनुमान चालीस कराएंगे?

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं। इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी, फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था?

सीएम योगी ने कहा कि इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था, हमने अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी की फिर से स्थापना की। 2017 से पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे।

सीएम योगी ने कहा प्रभु श्रीराम की कृपा और पवनसुत हनुमान जी का भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप बढ़ते दिखाई देता है। कोई सोचता था, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है।

भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया- सीएम योगी

अयोध्या में रैन बसेरा निषादराज गुह के नाम पर हो गया उनको यही बुरा लगता है कि निषादराज के नाम पर वो नहीं कर पाए। हमने तो यहां किया ही साथ ही श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा बनवा कर रखा है, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे। वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा किया, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही: सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि अच्छा विधायक चुना तो विकास दौड़ता हुआ दिखाई देता है, विकास चर्म पर दिखाई देता है। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद आगे आया हूं। मुझे 19 जून को रुद्धौली में आने का अवसर मिला था। विकास की योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो पहले असंभव था आज इन जनप्रतिनिधियों की वजह से संभव हो गया है। आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न बिजली, न सड़क, बगल में मां सरयू बह रही थी और अयोध्या इससे वंचित थी।

सूर्यवंश की राजधानी है अयोध्या- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या सोलर सिटी है, सूर्यवंश की राजधानी है। नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, गुप्तार घाट जो पहले उपेक्षित था, अब सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनर्रुद्धार किया है, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं। नीति स्पष्ट हो तो नियंता सहयोग करता है, आज ये अयोध्या में दिखाई देता है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 432 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस पर जमकर बोला।

संक्षेप

कांग्रेस ने वीबीएसए को बताया 'वेरी बैड शिक्षा एक्ट', चंद्रबाबू नायडू से क्यों की विरोध की अपील?

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों के लिए लाए जा रहे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। साथ ही कांग्रेस ने नए विधेयक को देश के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए खतरा बताते हुए इसे 'वेरी बैड शिक्षा एक्ट' करार दिया। यह विधेयक फिलहाल संसद की एक समिति के समक्ष विचाराधीन है और 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनडीए शासित राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश से इस विधेयक का विरोध करने की अपील की और संसद में इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत दिखाने की अपील की। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'वीबीएसए वास्तव में 'वेरी बैड शिक्षा एक्ट' साबित होगा। इसकी वजह है कि इसमें संविधान के दायरे से बाहर जाकर अधिकारों का विस्तार किया गया है, अनुदान परिषद का अभाव, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर असर होगा और इससे यूजीसी की परामर्श संबंधी व्यवस्था भी कमजोर होगी।' उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से इस विधेयक का विरोध करने की अपील करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू परिसीमन विधेयकों के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें उनका समर्थन करना पड़ा। रमेश ने कहा कि अब स्थिति बदल चुकी है। जयराम रमेश ने कहा, 'अब मोदी सरकार के अस्तित्व के लिए टीडीपी पहले जैसी जरूरी नहीं रह गई है, क्योंकि एनडीए में उसकी जगह तीन साल पुरानी, कम चर्चित और संदिग्ध 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' ने जगह ले ली है।

अभिषेक बनर्जी को चेतावनी- आवाज का नमूना दें, वरना सुरक्षा हटेगी

कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है। अदालत ने उन्हें बिधाननगर कोर्ट में उपस्थित होकर आपराधिक जांच विभाग (CID) के अधिकारियों को अपने आवाज के नमूने देने को कहा। ऐसा न करने पर एकल-न्यायाधीश पीठ नेता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से मिली सुरक्षा वापस ले लेगी। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बिधाननगर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। उन्हें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल पुलिस की CID को अपने आवाज के नमूने देने होंगे। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अभिषेक को अल्टीमेटम दिया। अभिषेक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। अदालत ने कहा कि यदि वह इस समय-सीमा का पालन नहीं करते और आवाज का नमूना देने के लिए जिला अदालत में पेश नहीं होते, तो कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी सहित पुलिस कार्रवाई से दी गई सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। अभिषेक पर हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए हिंसा भड़काने वाले बयान देने और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी देने का आरोप है।

'राम मंदिर बनाने का श्रेय लिया, तो चंदा चोरी का भी लें' : प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर क्या-क्या कहा?

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने राम मंदिर की स्थापना का श्रेय लिया है, तो संघ को चंदे की चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा 'अगर आपने राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लिया है, तो चंदा चोरी का श्रेय भी लें। पंजीकृत न होने और दक्षिणा लेने के कारण आपको इसमें से कितना मिला है? बंद कमरे में बहस करने के बजाय, सार्वजनिक रूप से सामने आएं। हमें बताएं कि चोर कौन हैं, आपको कितना मिला है, और आप और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं मोहन भगवत और बाकी सभी को चुनौती देता हूं।

यह घटना राम मंदिर के चंदे में कथित गबन के मामले के बीच सामने आई है, जिसने देशव्यापी विवाद को जन्म दिया है। इसके अलावा, खरगे ने विभिन्न परीक्षाओं में जारी अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि वे कब प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल की तरह नीट पेपर लीक पे चर्चा या ओएसएम पे चर्चा करेंगे।

उन्होंने सवाल उठाया 'सरकार की अक्षमता के कारण लाखों छात्रों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान कहां हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पिछले 10 वर्षों में करीब 90 पेपर लीक हुए हैं। सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है।

मासूम आरव हत्याकांड में बड़ा फैसला, बेरहम कातिल विराज को फांसी, सजा सुनते ही रो पड़ा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को दिनदहाड़े डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से सड़क पर आठ बार पटक कर हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। सजा सुनते ही विराज रोने लगा।

पुलिस अभिरक्षा में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पुलिस दोपहर ढाई बजे करीब जेल से कोर्ट लेकर पहुंची थी। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पूर्ण हैं। घटना बेहद जघन्य है। विराज को सजा का एलान होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई। इस दौरान उसके चेहरे पर सजा का खौफ साफ था। इधर, मृतक आरव की नानी पिंकी देवी भी पहुंची थी। उन्होंने सजा पर खुशी जताई।

शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई की दोपहर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने रिश्ते की भाभी रति से शादी करने की जिद पूरी न होने पर उसके डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को सड़क पर बेरहमी से आठ बार पटक-पटककर मार डाला था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। मूल रूप से अरांव निवासी रति देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण वह 5 महीने से मायके में रह रही थी।

अब ट्रेन टिकट बुकिंग होगी आसान!

नई आईआरसीटीसी वेबसाइट में आएंगे ये 4 बड़े बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्रेन टिकट बुकिंग को पहले से आसान, तेज और बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे जल्द ही नई आईआरसीटीसी वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करेगा। लॉन्च से पहले जयपुर स्थित एमएनआईटी के छात्रों को इसका डेमो दिखाया गया। इस दौरान छात्रों से फीडबैक लिया गया। रेलवे का कहना है कि छात्रों के सुझावों के आधार पर वेबसाइट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान बेहतर अनुभव मिल सके।

नई आईआरसीटीसी वेबसाइट को भारतीय रेलवे के नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। रिजर्वेशन सिस्टम का अपग्रेड भी साथ-साथ चल रहा है। ऐसे में नई सुविधाओं वाली आईआरसीटीसी वेबसाइट अगले कुछ महीनों में यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। दरअसल,एमएनआईटी जयपुर के छात्रों ने सबसे पहले आईआरसीटीसी वेबसाइट की कमियों की ओर ध्यान दिलाया था। इसी कारण 10 जुलाई को नई वेबसाइट के बीटा वर्जन की समीक्षा भी उन्हीं छात्रों से कराई गई। नई वेबसाइट के बीटा वर्जन में चार बड़े बदलाव किए गए हैं। यात्रियों को अब अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स नहीं होंगे। भारतीय रेलवे ने बताया, विभिन्न ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप्स को संचालित करने वाले करीब 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड के दौरान भी सिस्टम को लगातार चालू रखा गया।

'कुछ घाव भुलाए नहीं जा सकते', करूर पहुंचे सीएम विजय ने पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने का किया ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज करूर के दौरे पर हैं। ये वही जगह है जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय का ये पहला करूर दौरा है। यहां करूर में सीएम विजय ने 10 KM का रोड शो किया। इस दौरान सीएम विजय ने करूर हादसे में मरने वाले परिवारों में से 32 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी का लेटर भी दिया। इसके साथ ही 1700 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एक नॉन लेदर यूनिट की आधारशिला भी रखी।

वहीं करूर के एटलस ग्राउंड में पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद सीएम ने एक विशाल

जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वह भावुक हो गए और कहा कि जीवन की कोई भी सफलता निर्दोषों की जान जाने के दर्द को मिटा नहीं सकती। उन्होंने कहा, "जीवन में कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, दिल के कुछ दर्द और घाव कभी भुलाए नहीं जा सकते। सबसे अधिक जिस दर्द और घाव ने मुझे प्रभावित किया है, वह करूर की घटना है।"

'कार्यक्रम से पहले कोई चेतावनी नहीं दी'

हादसे से पहले की घटनाओं का वर्णन करते हुए सीएम ने कहा कि उनका राज्यव्यापी "जनता सम्मेलन" कार्यक्रम जनता से सीधे संवाद करने और उनकी चिंताओं को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ की आशंका के कारण पुलिस ने पहले ही उन्हें पेरंबालूर में एक कार्यक्रम रद्द करने की सलाह दी थी, लेकिन करूर में भारी भीड़ के बावजूद कार्यक्रम से पहले ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई।

'पुलिस ने हमें भीड़ के बारे में नहीं बताया'

सीएम विजय ने कहा, 'नमक्कल में हुई बैठक के बाद जब हम करूर आ रहे थे, तो क्या करूर पुलिस हमें सूचित नहीं कर सकती थी? अगर उन्हें लगता कि भीड़ को संभालना मुश्किल होगा, तो वे बैठक रद्द कर सकते थे। उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था। इसके बजाय, वे हमें कार्यक्रम स्थल तक ले गए।

डायबिटीज पीड़ितों के लिए भारत में लॉन्च हुई अनोखी दवा, इंसुलिन अब रोज नहीं हफ्ते में लेना होगा एक बार

नई दिल्ली, एजेंसी। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीक्ली नाम की नई इंसुलिन लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला बेसल इंसुलिन है, जो टाइप- 1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री- डायबिटीज है। फिलहाल देश में करीब 60 लाख लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं।

एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन दुनिया के कुछ देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। नई साप्ताहिक लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन आने से रोज लगने वाले बेसल इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी। हालांकि,

भोजन के बाद लगने वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत कई मरीजों में पहले की तरह बनी रह सकती है। प्रो. निश्चल ने कहा कि इस तरह की नई इंसुलिन की शुरुआत के दौरान सही डोज तय करने में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर बहुत कम होने) का खतरा भी रह सकता है। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर नवल विक्रम ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन पर कई देशों में अध्ययन हुए हैं और उनमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

डॉक्टर की सलाह जरूर लें

एम्स के प्रोफेसर ने कहा है कि हर ब्रांड की इंसुलिन की प्रभावशीलता और उसके क्लीनिकल परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी नई साप्ताहिक इंसुलिन पर जाने का फैसला मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। रोज लगने वाली इंसुलिन से साप्ताहिक इंसुलिन पर शिफ्ट करते समय डोज का सही निर्धारण और समय-समय पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है।

युवाओं में बढ़ रहा कम उम्र में जुए की लत का खतरा, सख्त नियमन और जागरूकता की आवश्यकता: अध्ययन

नई दिल्ली, एजेंसी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि युवाओं में कम उम्र में जुए की लत लगने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकारों को जुए के विज्ञापनों और इससे जुड़े उद्योग पर कड़े नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, परिवारों को भी अपने बच्चों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना होगा। मोनाश यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ चार्ल्स लिविंगस्टोन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में आठ प्रतिशत से अधिक वयस्क जुए के दुष्प्रभावों से प्रभावित हैं, जबकि लगभग एक प्रतिशत वयस्क अत्यधिक जोखिम वाले स्तर पर जुआ खेलते हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि 18 से 34 वर्ष के युवाओं को जुए की लत

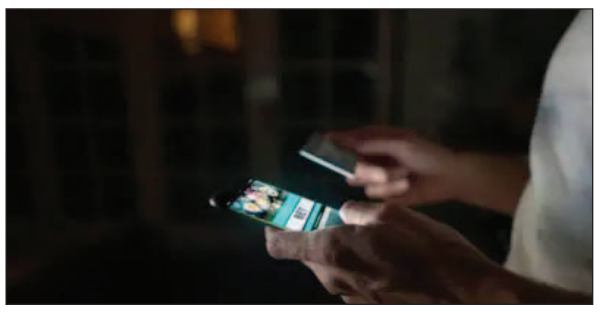

का सबसे अधिक जोखिम है। इस आयु वर्ग में नियमित रूप से पोकर मशीन जिन्हें पोकी कहा जाता है और ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले लगभग 90 प्रतिशत लोगों को गंभीर आर्थिक नुकसान, आपसी रिश्ते टूटने और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पोकर मशीन और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे जुए के कुछ रूप अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक नुकसानदेह हैं और इनसे लत लगने की आशंका बहुत अधिक रहती है। जुए से होने वाला सबसे आम नुकसान आर्थिक होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी जीवनभर की बचत या घर तक गंवा सकता है। इसके अलावा, जुआ मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे पछतावा, अपराधबोध, शर्म, मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। शोध के अनुसार, यह आदत आत्महत्या के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। जुए का नकारात्मक प्रभाव केवल खेलने वाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और कार्यस्थल पर भी पड़ता है। माता-पिता में जुए की लत का सीधा संबंध पारिवारिक हिंसा, वैवाहिक विवाद और बच्चों की उपेक्षा से पाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अमेरिकी मनोरोग संघ सहित अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा प्रणालियों ने जुए की लत को एक व्यवहार संबंधी विकार माना है, जिसमें व्यक्ति नुकसान होने के बावजूद अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाता। किशोरावस्था में मस्तिष्क के विकास के दौरान जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे छोटा पुरस्कार मिलने पर भी डोपामिन का स्राव होता है और लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण अब युवा बिना किसी कैसीनो गए, घर बैठे और परिवार की जानकारी के बिना भी जुआ खेल सकते हैं। अध्ययन में सामने आया है कि जुआ उद्योग आक्रामक विज्ञापनों और डेटा प्रोफाइलिंग के जरिए युवाओं को लक्षित करता है। इस खतरे को रोकने के लिए प्रस्तावित प्रतिबंधों को नाकाफी बताया गया है और विज्ञापनों पर अधिक प्रभावी नियमन की मांग की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैसी पद्धतियों से इसका उपचार संभव है, लेकिन सामाजिक शर्म के कारण लोग इलाज नहीं कराते।

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत आगामी 13 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सोमवार को अदालत की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस मामले में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने और राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का अनुरोध किया है। दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें इसी तरह के अनुरोध किए गए हैं। वहीं, तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। इससे पहले न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिकाकर्ता से मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए बाद की किसी तारीख पर सूचीबद्ध कराने का आग्रह करने को कहा था।

पर्यटन विभाग सवालों के घेरे में, धरोहरें बदहाल और जिम्मेदार बेखबर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक पर्यटन स्थल आज बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं लेकिन वर्षों से पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ) की नजर इन धरोहरों पर पड़ती ही नहीं दिखाई देती। धरातल पर विकास कार्य न के बराबर हैं, जबकि सरकारी दावों और प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं दिखाई देती।

जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बिजेथुआ महाबीरन धाम, धोपाप धाम, शिव धाम बेलवाई, लोहरामऊ शिव मंदिर, चांदा का सीताकुंड घाट, पारिजात वृक्ष और कुड़वार का ऐतिहासिक गढ़ा शामिल हैं। इन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कुड़वार स्थित ऐतिहासिक गढ़ा तक पहुंचने के लिए आज भी समुचित मार्ग नहीं है। यहां बौद्धकालीन कुआं, लाहौरी दीवारें और अन्य पुरातात्विक महत्व के अवशेष मौजूद हैं लेकिन उनकी ओर पर्यटन विभाग का ध्यान नहीं गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से केवल घोषणाएं और दावे सुनने को मिले धरातल पर काम नहीं। विडंबना यह है कि इन स्थलों की दुर्दशा को लेकर समय-समय पर समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रही हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने उनका संज्ञान लेने की भी जरूरत नहीं समझी। सवाल उठता है कि यदि वर्षों तक एक ही अधिकारी के पास विभाग का प्रभार रहा तो जिले के पर्यटन विकास के लिए आखिर क्या ठोस कार्य किए गए?

सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि पर्यटन मद की धनराशि का आवंटन कुछ निजी संस्थाओं को नियमों के विपरीत किया गया। यदि इन चर्चाओं में तथ्य हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किन संस्थाओं को किस आधार पर और किन नियमों के तहत धनराशि स्वीकृत की गई। यदि आरोप निराधार हैं तो प्रशासन को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पर्यटन विभाग का उद्देश्य केवल प्रचार-प्रसार तक सीमित रह गया है या फिर जिले की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के लिए भी कोई ठोस योजना बनाई जाएगी? जनता जवाब चाहती है कि करोड़ों रुपये की योजनाओं का लाभ आखिर जिले के पर्यटन स्थलों तक कब पहुंचेगा।

पदोन्नति प्राप्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया सम्मानित

4 बीईओ हुए वरिष्ठ प्रवक्ता डायट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। डायट परिसर में जनपद से चार खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त लेखाधिकारी को एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा के कर्मचारी और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्र के तमाम शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकारी को भावभीनी विदाई दी। समारोहों में शिक्षकों द्वारा बीईओ के कार्यकाल की सराहना की गई। उनके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में निभाए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीईओ को फूल-माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष रणबीर सिंह ने पदोन्नति पाकर वरिष्ठ प्रवक्ता डायट बनाए गए बीईओ के साथ व्यतीत कार्यों की सराहना करते हुए विशेष सम्मान व्यक्त किया। साथ ही सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी रहे नरेंद्र पाल सिंह के मूल विभाग में वापसी पर बधाई दी।मंच का संचालन कर रहे संतोष सिंह प्रतापगढ़ी ने बीईओ के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में ब्लॉक के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और उनका सहयोगात्मक रवैया हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में, समस्त बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से उन्हें एक सुंदर स्मृति चिह्न भेंट की गई। विदाई समारोह में पदोन्नति पाए खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों और कर्मचारियों से जो प्यार और सहयोग यहाँ मिला है, उसे वो अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। शिक्षा का असल उद्देश्य तभी पूरा होता है जब पूरी टीम एक परिवार की तरह काम करे।इस मौके पर समस्त बी ई ओ, कार्यालय सहायक सहित शिक्षक उपस्थित रहे।

सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि

सफल सर्जरी कर निकाला 10 किलो का ट्यूमर, मरीज को मिला नया जीवन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन कर जिले के चिकित्सा क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। यहां के कुशल सर्जनों की टीम ने एक मरीज के शरीर से 10 किलोग्राम का एक विशाल और जानलेवा ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर उसे नई जिंदगी दी है।

29 वर्षीय महिला पिछले काफी समय से गंभीर दर्द और शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी। कई जगह इलाज के बाद भी जब कोई समाधान नहीं मिला तो मरीज स्वशासी मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर के सर्जरी विभाग में पहुंचा। यहां वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा की गई जांच में एक विशाल ट्यूमर होने की पुष्टि हुई, जो मरीज की जान के लिए खतरा बन चुका था। ट्यूमर का आकार अत्यधिक बड़ा होने और महत्वपूर्ण नसों से जुड़े होने के कारण यह सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ सुकेश और डॉ सुप्रीत के नेतृत्व में सर्जरी विभाग की टीम ने इस चुनौती को स्वीकारा। इस जटिल ऑपरेशन के बाद, डॉक्टरों ने 10 किलो जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 और मोटाई 10 सेंटीमीटर के भारी-भरकम ट्यूमर को शरीर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस ऐतिहासिक सर्जरी को सफल बनाने में मुख्य सर्जन डॉ सुकेश और डॉ सुप्रीत, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. ऐश्वर्या, डॉ. अमित और नर्सिंग स्टाफ सिस्टर नसीमा, कामिनी, शीलम, प्रतिभा, साहलिया की अहम भूमिका रही। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है और वह तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। स्वशासी मेडिकल कॉलेज की इस अभूतपूर्व सफलता की पूरे जिले में व्यापक चर्चा हो रही है और स्थानीय लोग डॉक्टरों की इस टीम की जमकर सराहना कर रहे हैं।

पदोन्नति प्राप्त चार खंड शिक्षा अधिकारियों को दी गई भावभीनी विदाई

सुल्तानपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर में जनपद के चार खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) बनने पर सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने की। समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। पदोन्नति प्राप्त करने वालों में खंड शिक्षा अधिकारी अजय सिंह (लंभुआ), रामतीर्थ वर्मा (दूबेपुर), अरविंद कुमार यादव (धनपतगंज) तथा सुधीर सिंह (जयसिंहपुर) शामिल रहे। चारों अधिकारियों को पदोन्नति के साथ पीईएस रैंक प्रदान करते हुए वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) के पद पर नियुक्ति मिली। वहीं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के मूल विभाग में वापसी पर भी उन्हें सम्मानित किया गया।

कुड़वार ब्लॉक की प्रतापपुर ग्रामसभा में बदहाल व्यवस्था

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कुड़वार विकास खंड की ग्रामसभा प्रतापपुर के पूरे जुराम तिवारी का पुरवा में सड़क पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण ग्रामीणों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को रोजाना इसी जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामसभा में तैनात सफाईकर्मी लंबे समय से नदारद है। नियमित सफाई न होने के कारण नालियां जाम हैं और गंदा पानी सड़क पर फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रामसभा में समाज सेवी जनप्रतिनिधियों की अच्छी-खासी संख्या होने के बावजूद आज तक इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाने का प्रयास नहीं किया गया। गांव के लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) तथा संबंधित अधिकारी आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और प्रशासनिक उदासीनता के चलते ग्रामीणों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

जिला पंचायत परिसर से वृहद वृक्षारोपण अभियान का आगाज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जिला पंचायत परिसर में उत्साह और जनसहभागिता के साथ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने का आह्वान किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। पौधरोपण के उपरांत जिला पंचायत सभागार में आयोजित गोष्ठी में अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने कहा कि एक पेड़, अनेक पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील करते हुए अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार चतुर्वेदी, पवन कुमार, बद्रीनाथ यादव, मो.निसार, मो.आसिफ खान, दिनेश कुमार यादव, चंदन यादव, नरेश चंद्र उपाध्याय एवं रामशंकर यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी,अभियंता,कार्य अधिकारी, अवर अभियंताओं तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संयोजन प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया।

यूपी में 20 आईएएस का ट्रांसफर, हटाए गए नोएडा के जीएसटी एडिशनल कमिश्नर संदीप भागिया... ये बड़े चेहरे भी लिस्ट में शामिल

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कल देर रात जारी आदेश के अनुसार कई सीनियर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं नोएडा में जीएसटी एडिशनल कमिश्नर रहे संदीप भागिया को हटा दिया गया है।आइए जानते हैं कि किस आईएएस अधिकारी को किस विभाग में नई तैनाती मिली है। नोएडा में 12 जून को हुई जीएसटी समीक्षा बैठक के दौरान संदीप भागिया पर आरोप लगा था कि उन्होंने उपायुक्त खंड-12 वेदप्रकाश के साथ समीक्षा बैठक में गाली-गलौज की, गुस्से में पेन फेंका, वेदप्रकाश की तबियत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहीं राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव सुधा वर्मा का भी तबादला किया है। वह 1 जनवरी 2026 को ही राजस्व विभाग की सचिव बनी थीं, मात्र 6 महीने 9 दिन में ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर लिस्ट में सचिव स्तर से लेकर नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त और मिशन निदेशक स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास, वन एवं पर्यावरण, नगर विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन, ऊर्जा और गन्ना विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव किए गए हैं।

डॉ. सारिका मोहन को महानिरीक्षक, निबंधन बनाया गया है, जबकि नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा विभाग में महानिदेशक एवं सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सुश्री सुधा वर्मा को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। वहीं दीपा रंजन को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों, नगर आयुक्तों और अपर आयुक्तों के भी तबादले किए गए हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।

तबादला सूची के अनुसार सुधा वर्मा को सचिव, राजस्व विभाग से हटाकर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। डॉ। सारिका मोहन को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्थानांतरित कर महानिरीक्षक, निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नेहा शर्मा को महानिदेशक, निर्वाचन के पद से चिकित्सा शिक्षा विभाग का महानिदेशक एवं सचिव बनाया गया है। अरुण कुमार को अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नियुक्त किया गया है। वहीं जे। रीभा को उनके वर्तमान पद के साथ अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दीपा रंजन को मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से विशेष सचिव, संस्कृति विभाग बनाया गया है। संजय कुमार सिंह-1 को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग एवं निदेशक, धर्मार्थ कार्य के पद पर रहते हुए निदेशक, संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि विशाल सिंह को निदेशक, संस्कृति के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। रिया केजरीवाल को प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ से विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग नियुक्त किया गया है। वहीं संदीप भागिया को अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद द्वितीय से स्थानांतरित कर प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाया गया है।

राज्य कर विभाग के गौतमबुद्ध नगर जोन के अपर आयुक्त 2018 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप भागिया को भी हटा दिया गया। उनके खिलाफ 60 अधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव एसपी गोयल को शिकायत की थी। आरोप था कि वह अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हैं। 12 जून को एक बैठक में उनकी डांट पड़ने के बाद एक अधिकारी वेद प्रकाश सिंह की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए थे। संदीप भागिया को अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का प्रबंध निदेशक बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

यूपी में बारिश बनी आफत! 14 की मौत, 46 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दे रही है, वहीं कई जिलों में यह बारिश आफत बनकर बरसी है। गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने, दीवार ढहने और अन्य दुर्घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर जलभराव, सड़कें बंद होने और संपर्क मार्ग टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 46 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। 13 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी मानसूनी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है।

बारिश से 14 लोगों की मौत

बारिश से जुड़े हादसों में सबसे अधिक मौतें पूर्वांचल में हुई हैं। गोरखपुर और बस्ती मंडल में बिजली गिरने से आठ लोगों की जान चली गई, जबकि बुलंदशहर में दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। अन्य जिलों में भी बारिश से जुड़े हादसों में लोगों की जान गई है।

इन जिलों में स्कूल बंद

भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अब तक जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है:

मेरठ कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद।

मुजफ्फरनगर नर्सरी से 12वीं तक अवकाश।

बिजनौर सभी विद्यालय बंद।

सहारनपुर सभी स्कूलों में छुट्टी।

बुलंदशहर नर्सरी से 12वीं तक अवकाश।

गाजियाबाद नर्सरी से 12वीं तक सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद।

कासगंज नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल बंद।

46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं समेत आसपास के क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा और औरैया के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में रिकॉर्ड बारिश

बीते 24 घंटे में बिजनौर के नजीबाबाद में 306 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो वर्ष 1952 के बाद तीसरी सबसे अधिक बारिश है। इसके अलावा...

एटा में 222 मिमी
संभल में 204 मिमी
आगरा में 146 मिमी
महाराजगंज में 104 मिमी
सिद्धार्थनगर में 78.6 मिमी

तापमान में बड़ी गिरावट

लगातार बारिश के चलते कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया। अलीगढ़ में तापमान 9.4 डिग्री, मेरठ में 8.3 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 7.6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। कानपुर, इटावा और बरेली में भी तापमान में गिरावट आई।

राजधानी लखनऊ में भी तेज बारिश

राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहर में 27.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को लखनऊ के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 13 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

12 जुलाई को सुलतानपुर में 53.15 लाख पौधों का होगा वृहद वृक्षारोपण, तैयारियों की समीक्षा

सुल्तानपुर। अयोध्या मंडल के मण्डलायुक्त एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में 12 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम की तैयारियों को लेकर जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारू निगम, संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 53,15,700 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित है तथा 97 प्रतिशत पौधों का नर्सरियों से उठान किया जा चुका है। वृक्षारोपण अभियान 12 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मण्डलायुक्त ने सभी विभागों को समय से तैयारियां पूरी करने, पौधरोपण के बाद 100 प्रतिशत जियो टैगिंग कराने और अगले दिन तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बीकापुर में स्व. मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण, सीएम ने लाभार्थियों को वितरित किए प्रमाणपत्र और सहायता

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीकापुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता, प्रमाणपत्र, टूलकिट, आवास की चाबी और अन्य सामग्री वितरित की तथा बच्चों के साथ आत्मीय संवाद भी किया।मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने संघर्ष और जनसेवा के बल पर अलग पहचान बनाई। उन्होंने सिंचाई विभाग के माध्यम से किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए और अपना पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पुत्र एवं बीकापुर विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र के विकास और डबल इंजन सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र की समस्याओं को लगातार सरकार के सामने रखते हैं और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीर-वीरांगनाओं और महापुरुषों की वेशभूषा में सजे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों से संवाद किया, उनके साथ हंसी-मजाक किया तथा उन्हें चॉकलेट और उपहार भेंट किए। भगत सिंह की वेशभूषा में आए एक बच्चे से मुख्यमंत्री ने हाथ में सेब दिखाते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि यह आलू है क्या, जिस पर बच्चों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह सेब है।मुख्यमंत्री ने अन्नप्राशन संस्कार कार्यक्रम में भी भाग लिया और नन्हे बच्चों को गोद में लेकर उन्हें चंदन लगाया तथा अन्नप्राशन कराया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बच्चों को खिलौने भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान शिव के मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अनुराधा दुबे और अंजू को 11 करोड़ रुपये से अधिक राशि का चेक प्रदान किया गया। विद्युत सखी योजना के अंतर्गत वर्षा को थर्मल प्रिंटर तथा किरण और पूजा सिंह को विद्याशक्ति किट दी गई। बैंक सखी योजना के तहत अनिता पाल को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सोनी मौर्या और पिंकी को आवास की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अवनीश मिश्र को 4.18 लाख रुपये तथा अमित गौतम को 3 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थी शिवपूजन को प्रशस्ति पत्र दिया गया।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पंकज कुमार और विकास को टूलकिट वितरित की गई। आलोक कुमार वर्मा और अशोक कुमार को उर्वरा वर्मी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध कराई गई, जबकि रीता सिंह और महावीर सिंह को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ में 110 वार्डों में चला मेगा सफाई अभियान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम ने पूरे शहर में वृहद मेगा सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत नगर निगम के सभी 110 वार्डों में एक साथ विशेष सफाई अभियान संचालित कर स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ लखनऊ का संदेश दिया गया।अभियान का शुभारंभ महापौर सुषमा खर्कवाल ने हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पार्षदों और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद महापौर स्वयं सफाई अभियान में शामिल हुईं और नागरिकों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा शहर को साफ-सुथरा रखने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।महापौर ने कहा कि राजनाथ सिंह का लखनऊ के प्रति विशेष स्नेह, जनसेवा की भावना और शहर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित यह मेगा सफाई अभियान सेवा, सम्मान और स्वच्छता के संकल्प का प्रतीक है।उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सहभागिता से ही लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों में अग्रणी बनाया जा सकता है।अभियान के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार, पार्षद, अपर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक सफाई अभियान में भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया।मेगा सफाई अभियान को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने सभी 110 वार्डों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की। इन अधिकारियों को अपने-अपने वार्डों में सफाई कार्यों की निगरानी, अभियान के प्रभावी संचालन तथा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

ईसाई समुदाय पर हमलों को लेकर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश के विभिन्न राज्यों में ईसाई समुदाय और उनके प्रार्थना स्थलों पर कथित हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर गंभीर चुनौती हैं।संजय सिंह ने पत्र में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में ईसाई समुदाय के खिलाफ हुई कथित हिंसा और चर्चों पर हमलों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से इन घटनाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चों पर हमले, पादरियों के साथ मारपीट और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं पर केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।आप सांसद ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पुलिस हमलावरों के बजाय पीड़ितों पर ही धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इसे न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।संजय सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार देता है।

संक्षेप

वृंदावन योजना में भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व संपत्ति प्रबंधक से 83.40 लाख की होगी वसूली, पेंशन भी आधी

लखनऊ। वृंदावन योजना के आवासीय व कमर्शियल भूखंड बेचने में भ्रष्टाचार करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व नकदीकरण के साथ ही अब पेंशन से भी वसूली होगी। लखनऊ ही नहीं प्रदेश की अन्य योजनाओं में कार्यरत रहे छह कार्मिकों का प्रकरण निस्तारित करने पर बोर्ड ने मुहर लगा दिया है। अपर आवास आयुक्त व सचिव डा. नीरज शुक्ल ने पत्रकारों को बताया, वृंदावन योजना की विभिन्न संपत्तियों की बिक्री करने में गंभीर अनियमितताएं करने पर तत्कालीन संपत्ति प्रबंधक केडी शर्मा की जांच के लिए 25 फरवरी 2022 को समिति गठित की गई थी। उन पर आरोप सही मिलने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर फिर से जांच करने का आदेश हुआ। उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन ने सेवानिवृत्त संपत्ति प्रबंधक की ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण व अन्य देयकों से 83 लाख 40 हजार 877 रुपये वसूल करने का आदेश दिया था। बची धनराशि की कटौती करने के लिए उनकी पेंशन में 50 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया, पेंशन से अधिकतम इतनी ही कटौती की जा सकती थी, उस पर बोर्ड ने मुहर लगा दिया है।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड : एसआइटी की जांच की आंच में आए आइएएस प्रभुनाथ सिंह और अभिषेक प्रकाश, एलडीए ने भेजे नाम

लखनऊ। अलीगंज सेक्टर डी में अवैध बिल्डिंग अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में एसआइटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने परिवहन निगम के मौजूदा प्रबंध निदेशक प्रभुनाथ सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव पद पर तैनात आइएएस अभिषेक प्रकाश के नाम भी भेजे हैं। ये दोनों एलडीए उपाध्यक्ष पद पर तैनात रह चुके हैं। बुधवार को नौ आइएएस व नौ पीसीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। असल में 2016 से 2024 तक एलडीए में तैनात रहे अधिकारियों की विस्तृत सूची एसआइटी को दी गई है। अब एसआइटी टीम के अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार इनमें से जिम्मेदारों का नाम खंगालेंगे।सूत्र बताते हैं कि एसआइटी ने अग्निशमन और बिजली विभाग से भी ऐसे ही अधिकारियों की सूची मांगी है। पहली बार आइएएस व पीसीएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। इससे अधिकारियों में खलबली मची है। कई अधिकारी कहते सुने गए कि सिर्फ तैनाती की वजह से एसआइटी को नाम भेजना उचित नहीं है।

लखनऊ सहित अवध के जिलों में सुबह से बारिश, मानसून में उत्तर प्रदेश , सभी जिलों में जमकर बरस रहे हैं बादल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से वर्षा जारी है। मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दिनभर की उमस और गर्मी से राहत मिलने पर लोगों का रुख चाट, टिक्की और पकौड़ी की दुकानों की ओर हो गया। खानपान की दुकानों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ दिखी। हजरतगंज, गोमतीनगर, चौक और निशातगंज समेत कई इलाकों में लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने शुक्रवार व शनिवार को लखनऊ समेत 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से बना सक्रिय मौसम तंत्र मध्य प्रदेश के समीप पहुंच चुका है। इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर दिखने लगा है। यही वजह है कि पूरब से पश्चिम तक झमाझम बारिश हो रही है।

लखनऊ में युवक के कमरे पर युवती ने की आत्महत्या, मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों की हुई थी दोस्ती

लखनऊ। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 18 स्थित गोवर्धन एनक्लेव में गोंडा से अपने दोस्त के घर आई युवती ने दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान गोंडा जिले के तरबगंज निवासी 30 वर्षीय प्रतिभा के रूप में हुई है। वह गोंडा स्थित एक मेडिकल संस्थान में कार्यरत थी।

इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिभा की दोस्ती कुछ समय पहले वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से पीजीआई अस्पताल में तैनात नर्स विकास त्रिपाठी से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जिसके बाद प्रतिभा बुधवार को विकास से कुछ नोट्स लेने गोवर्धन एनक्लेव स्थित उनके किराये के मकान पर आई थी।

यूपी सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, कई को नई जिम्मेदारियां

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार और कुछ को पूर्व प्रभार से मुक्त किया गया है।जारी आदेश के अनुसार, सुधा वर्मा को श्रमायुक्त बनाया गया है। डॉ. सारिका मोहन को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के साथ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। नेहा शर्मा को महानिरीक्षक, निबंधन बनाया गया है।अरुण कुमार को अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जे. रीभा को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग बनाया गया है। दीपा रंजन को मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नियुक्त किया गया है।संजय कुमार सिंह-1 को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग के पद पर तैनात किया गया है। विशाल सिंह को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए निदेशक, संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रिया केजरीवाल को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग बनाया गया है।संदीप भागिया को प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), लखनऊ नियुक्त किया गया है। परीक्षित खटाना को अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर तथा राकेश कुमार पटेल को मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ बनाया गया है।रेणु तिवारी को विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में तैनाती दी गई है। जगप्रवेश को नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन नगर निगम बनाया गया है। ओजस्वी राज को मुख्य विकास अधिकारी, बलिया नियुक्त किया गया है।आलोक कुमार को अपर आयुक्त, राज्य कर, गाजियाबाद प्रथम, अजय कुमार गौतम को मुख्य विकास अधिकारी, इटावा तथा संजय कुमार सिंह को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद बनाया गया है।प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी मनिकंदन ए. को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर के पद पर तैनात किया गया है। वहीं डॉ. वंदना वर्मा को विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के साथ संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें, कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करें: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन वर्गों की समस्याओं का स्थायी समाधान सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेने में है।लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों और वंचित वर्गों को संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार दिलाने के साथ यह भी संदेश दिया था कि उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई संविधान और कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया।

बीबीएयू ने यूजी प्रवेश विवरणिका जारी की, 14 जुलाई से समर्थ पोर्टल पर शुरू होगा पंजीकरण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश विवरणिका (यूजी प्रॉस्पेक्टस) जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की ओर से अनुमोदित विवरणिका के अनुसार 14 जुलाई 2026 से समर्थ (Samarth) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होगा। सभी प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) की मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि बीबीएयू अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान, नवाचार और छात्र-केंद्रित शिक्षण व्यवस्था के कारण देश के अग्रणी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को एनएएसी (NAAC) से ए++ ग्रेड प्राप्त है तथा एनआईआरएफ (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में 37वां स्थान मिला है। आधुनिक अधोसंरचना, हरित एवं समावेशी परिसर तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे प्रवेश विवरणिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर निर्धारित समय के भीतर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करें।प्रवेश प्रकोष्ठ समिति के अध्यक्ष प्रो. अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय के 27 स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल 1528 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इनमें लखनऊ परिसर के 20 पाठ्यक्रमों में 958 सीटें तथा अमेठी सैटेलाइट परिसर के 7 पाठ्यक्रमों में 570 सीटें शामिल हैं। प्रवेश विवरणिका में सभी पाठ्यक्रमों की पात्रता, सीटों की संख्या, शुल्क, आरक्षण, आवश्यक दस्तावेज और प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को बीए (ऑनर्स) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम (ऑनर्स), बीबीए (ऑनर्स), बीबीए एलएलबी (ऑनर्स), बीएससी, बीटेक सहित विभिन्न रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन का अवसर मिलेगा। पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क से संबंधित विस्तृत अधिसूचना विश्वविद्यालय जल्द जारी करेगा।विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय को एनएएसी से ए++ ग्रेड प्राप्त है तथा एनआईआरएफ रैंकिंग में विश्वविद्यालय श्रेणी में 37वां स्थान हासिल हुआ है। विषयवार रैंकिंग में विधि 12वें, फार्मेसी 23वें, हॉर्टिकल्चर 21वें और प्रबंधन 79वें स्थान पर रहा है।बीबीएयू की प्रमुख विशेषताओं में आईएसओ 14001:2015 प्रमाणित ग्रीन कैंपस, समृद्ध जैव विविधता, पंचकोश आधारित शिक्षण प्रणाली, हॉबी क्लब, ₹उम्मीद₹ होलिस्टिक वेलबीइंग पहल, विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला, उद्योग-अकादमिक सहयोग, समानता एवं समावेशिता पर आधारित शिक्षण वातावरण तथा आधुनिक अधोसंरचना शामिल हैं।

12 जुलाई से शुरू होगा 'मेरी पंचायत : हरित पंचायत अभियान', 57 हजार ग्राम पंचायतों में लगेंगे 1.42 करोड़ पौधे

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में 12 जुलाई से वृहद वृक्षारोपण अभियान-2026 के तहत पंचायती राज विभाग 'मेरी पंचायतः हरित पंचायत अभियान' की शुरुआत करेगा। अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में 1.42 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास का सशक्त केंद्र बनाना है।

अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें पर्यावरण संरक्षण को ग्राम पंचायतों के विकास एजेंडा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। ग्राम सभाओं में चारागाहों, तालाबों, अमृत सरोवरों, वेटलैंड क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का चिन्हांकन कर व्यापक वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना में हरित विकास से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।पंचायत भवनों, विद्यालयों, सामुदायिक परिसरों, सड़क किनारों, तालाबों, अमृत सरोवरों, चारागाहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, सहजन और विभिन्न फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड, नियमित सिंचाई और उनके संरक्षण की सतत निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान के दौरान 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे जनभागीदारी कार्यक्रमों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही रोपित पौधों की सुरक्षा को सामुदायिक जिम्मेदारी के रूप में विकसित किया जाएगा।यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वर्षा जल संचयन, तालाबों और कुओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गोबर गैस और सामुदायिक कम्पोस्टिंग को बढ़ावा, सौर ऊर्जा के उपयोग का विस्तार, जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता, पराली प्रबंधन तथा ड्रिप सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों को भी प्रोत्साहित करेगा।अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम सभाओं की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। वृक्षारोपण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का फोटो और वीडियो प्रलेखन किया जाएगा तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा।पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'मेरी पंचायतः हरित पंचायत अभियान' ग्राम पंचायतों में जनसहभागिता आधारित हरित विकास की नई कार्यसंस्कृति स्थापित करेगा और पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन तथा स्वच्छता को ग्रामीण विकास का अभिन्न हिस्सा बनाएगा।पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन से लेकर पौधारोपण, पौध संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

रहीमाबाद में युवती से दुष्कर्म का आरोपी छह घंटे में गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रहीमाबाद थाना पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को घटना की सूचना मिलने के लगभग छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने रहीमाबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को अमित उर्फ रजनीश उर्फ कृष्णा निवासी ग्राम उमरावल, थाना रहीमाबाद, 9 जुलाई को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।तहरीर के आधार पर थाना रहीमाबाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) एवं 65(2), पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्रिगुनायक के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने संभावित स्थानों पर सघन तलाश, मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद ग्राम अहिंडर और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया। तलाश के दौरान ग्राम उमरावल स्थित सड़क किनारे तालाब के पास से आरोपी अमित उर्फ रजनीश उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया।पुलिस ने बताया कि पीड़िता का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले की विवेचना और अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट, चोरी, महिलाओं से संबंधित अपराध, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट तथा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में सात मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान मामला उसके खिलाफ दर्ज आठवां आपराधिक मुकदमा है।

समंदर बन गई हैं महानगरों की सड़कें, डूबती गाड़ियों को कोई किनारा नहीं मिलता

हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं। हम आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट शहरों और वैश्विक स्तर की सुविधाओं का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या हर मॉनसून हमारे इन सभी दावों की वास्तविकता सामने नहीं रख देता? क्या यह सवाल पूछने का समय नहीं आ गया है कि यदि हमारे महानगर और राज्य की राजधानियां कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पा रही हैं, तो विकसित भारत की बुनियाद आखिर कितनी मजबूत है? दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गुरुग्राम जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र हर वर्ष मानसून आते ही जलभराव, जाम और अव्यवस्था की पहचान बन जाते हैं? क्या यह केवल मौसम की मार है, या फिर हमारी नगर योजना, निर्माण व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी की सबसे बड़ी असफलता है? यदि हर वर्ष यही स्थिति बननी है, तो फिर हर वर्ष होने वाली तैयारियों और बैठकों का परिणाम आखिर कहां दिखाई देता है?

क्या स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें, चमकदार भवन और आकर्षक परियोजनाएं हैं? क्या स्मार्ट शहर वह नहीं होना चाहिए जो सामान्य से अधिक बारिश को भी सहजता से संभाल सके? यदि अरबों रुपये जल निकासी, सड़क निर्माण और शहरी विकास पर खर्च हो रहे हैं, तो पहली तेज बारिश में ही सड़कें नदी और चौराहे तालाब क्यों बन जाते हैं?

क्या हर मानसून के बाद वही तस्वीरें, वही बयान और वही आश्वासन सुनना हमारी नियति बन चुकी है? क्या कभी किसी अधिकारी, किसी एजेंसी या किसी निर्माण करने वाली संस्था की जवाबदेही तय हुई? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि हर वर्ष खर्च होने वाला धन आखिर किस काम में लगाया जाता है?

क्या समस्या केवल अधिक बारिश की है, या फिर प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण, बिना योजना के विस्तार, कमजोर निर्माण और रखरखाव की अनदेखी इसकी असली वजह है? क्या नदियों, तालाबों और पुराने जल निकासी मार्गों को पाटकर खड़ी की गई इमारतों की कीमत अब पूरा समाज नहीं चुका रहा है? यदि शहरों की सांस लेने वाली प्राकृतिक व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो पानी आखिर जाएगा कहां?

क्या यह सामान्य बात मानी जा सकती है कि बारिश होते ही एंबुलेंस फंस जाए, बच्चे स्कूल न पहुंच सकें, कर्मचारी दफ्तर न जा सकें, बाजार ठप हो जाएं, रेल और हवाई यात्रा थम जाएं और सामान्य जीवन रुक जाए? क्या हर वर्ष होने वाले आर्थिक नुकसान, समय की बर्बादी और जनजीवन की परेशानी का कोई हिसाब भी रखा जाता है? यदि रखा जाता है, तो फिर समाधान आज तक क्यों नहीं मिला?

क्या विकसित भारत केवल बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे और गगनचुंबी इमारतों से बनेगा? या फिर उसकी पहचान ऐसी मजबूत बुनियादी व्यवस्था से होगी जो हर मौसम में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम जीवन दे सके? क्या विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना उन शहरों के सहारे पूरा होगा जो हर मानसून में ठहर जाते हैं?

क्या केवल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाना पर्याप्त है? क्या नागरिकों की भी जिम्मेदारी नहीं कि वे नालों में कचरा न डालें, जलमार्गों पर अतिक्रमण का विरोध करें और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं? लेकिन क्या यह भी उतना ही सच नहीं कि व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पर होती है जिसके हाथ में योजना, संसाधन और निर्णय की शक्ति होती है?

देखा जाये तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम 2047 के विकसित भारत की इमारत उस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं जो हर मानसून में हिल जाती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि विकास के दावों से पहले शहरों की जल निकासी व्यवस्था, निर्माण की गुणवत्ता, नगर नियोजन और प्रशासनिक जवाबदेही को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए? क्या जनता को हर वर्ष एक ही परेशानी झेलने के लिए मजबूर रखना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान हो सकती है? और यदि इन सवालों का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या हमें पहले विकसित भारत का सपना देखना चाहिए, या पहले उसकी मजबूत बुनियाद तैयार करनी चाहिए?

स्वस्थ व सशक्त समाज का निर्माण परिवार नियोजन के साथ

विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) पर विशेष

मुकेश कुमार शर्मा

युवाओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए ही शादी के बाद शगुन किट के माध्यम से परिवार नियोजन साधनों की जानकारी के साथ ही जरूरी परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

समाज की प्रथम इकाई परिवार यदि स्वस्थ और खुशहाल बनेगा तभी सशक्त समाज के सपने को साकार किया जा सकता है। परिवार तभी स्वस्थ बनेगा जब घर के बड़े-बुजुर्ग, बच्चे, किशोर-किशोरियां, महिलाएं और युवक अपने को स्वस्थ रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। उसी का एक बड़ा पहलू है कि परिवार में नए मेहमान यानि बहू या नन्हें-मुन्ने के आगमन के सही समय का अवश्य ख्याल रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो शादी की सही उम्र 21 साल के बाद ही बेटी को विवाह के बंधन में बाँधने की योजना बनाएं। शादी के दो से तीन साल के बाद ही परिवार बढ़ाने या संतानोत्पति के बारे में विचार करें। शादी के दो-तीन साल तक पति-पत्नी एक-दूसरे को भलीभांति समझें और परिवार को बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी पूँजी भी जुटा लें।

युवाओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए ही शादी के बाद शगुन किट के माध्यम से परिवार नियोजन साधनों की जानकारी के साथ ही जरूरी परामर्श भी प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर बैठे परिवार नियोजन साधनों की पहुँच आसान बनाने की कोशिश रहती है। ऐसे में स्पष्ट है कि परिवार नियोजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर ही है। युवाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की अलख जगाने की सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हुए, इस साल विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) की थीम 'युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना -आज और भविष्य के लिए' तय की गयी है।

आज विश्व में करीब 147 करोड़ की आबादी के साथ भारत जनसंख्या के मामले में अग्रिम पायदान पर खड़ा है, जबकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जरूरी है कि हम परिवार के आकार को नियोजित रखने की हरसम्भव कोशिश करें। ऐसे में विश्व जनसंख्या दिवस पर युवाओं को स्वस्थ और खुशहाल परिवार के प्रभावी उपायों के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला जरूरी उपाय यही है कि शादी के पश्चात गर्भधारण की योजना 21 साल की उम्र के बाद ही बनाएं। दो बच्चों के जन्म के बीच कम से कम तीन साल का अंतर जरूर रखें ताकि महिला का शरीर पुनः गर्भधारण के योग्य बन पाए। इसके अलावा इस दौरान बच्चे का लालन-पालन भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। परिवार का आकार नियोजित रखने के लिए ही "बास्केट ऑफ़ च्वाइस" का सुरक्षित और प्रभावी विकल्प युवाओं के पास मौजूद है। इसलिए अपने मनमुताबिक़ परिवार नियोजन के साधन का चयन कर सही समय पर ही संतान की योजना आसानी से बनायी जा सकती है।

परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए ही स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का आयोजन किया जाता है। समय-समय पर सास-बेटा-बहू सम्मेलन के साथ ही अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में परामर्श के साथ ही परिवार नियोजन के साधनों के फायदे और उनकी उपलब्धता के बारे में भी बताया जाता है। परिवार नियोजन के मौजूदा विकल्पों में त्रैमासिक गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा को अपनाकर न केवल मां और शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती है, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल परिवार की नींव भी रखी जा सकती है। इसका एक इंजेक्शन तीन माह तक अनचाहे गर्भधारण से छुटकारा दिलाता है। यह इंजेक्शन बहुत ही आसान और सुविधाजनक भी है। यह समस्त राजकीय चिकित्सा इकाइयों पर निःशुल्क उपलब्ध भी है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखने के लिए अस्थायी साधन के तहत ओरल पिल्स, पुरुष कंडोम, आईयूसीडी प्रसव पश्चात/ गर्भ समापन पश्चात आईयूसीडी व हार्मोनल गोली छाया (सैंटोक्रोमान) उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन किट (कंडोम बॉक्स) की भी व्यवस्था की गयी है ताकि पुरुषों को बिना झिझक वहां से कंडोम या महिलाओं को अन्य परिवार नियोजन के साधन प्राप्त करने में आसानी हो। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर परिवार नियोजन के स्थायी साधन के तहत महिला व पुरुष नसबंदी की सेवा उपलब्ध है, जो कि परिवार पूरा होने पर अपनाई जाने वाली सबसे सुरक्षित और कारगर सेवा है। शारीरिक बनावट के मुताबिक़ महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी बेहद सरल और सुरक्षित है। इसमें महज कुछ मिनट लगते हैं। नसबंदी के दो-तीन दिन बाद पुरुष अपने काम पर भी आराम से जा सकते हैं जबकि महिलाओं को कम से कम एक हफ्ते तक पूरी तरह से आराम की जरूरत होती है।

परिवार नियोजन के जब इतने सारे साधन मौजूद हैं तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि खूब सोच-समझकर और आपस में बात करके ही बच्चे की योजना बनायें। खासकर युवाओं को यह जानना जरूरी है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जिस तरह आपस में बात करना जरूरी होता है, उसी तरह से स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हरहाल में बात करें। पति-पत्नी आपस में बात करें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए किस साधन को अपनाना बेहतर होगा। परिवार पूरा होने पर कौन सा साधन अपनाना है और यह सुविधाएँ किस तरह के स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त की जा सकती हैं। परिवार नियोजन के इतने सारे साधनों की मौजूदगी के बाद भी अनचाहे गर्भधारण और गर्भपात जैसे जोखिम भरा कदम उठाने में किसी की भलाई नहीं है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर युवाओं को इस बारे में भी जागरूक करना जरूरी है कि युवा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए वह इस तरह के जोखिम से दूर ही रहें और परिवार नियोजन के सुरक्षित तरीकों को प्राथमिकता दें। आर्थिक अनिश्चितता, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन के दबावों आदि से घिरे युवाओं को अपने आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी विचार करना जरूरी है, इसमें परिवार नियोजन हरहाल में उनको मजबूती प्रदान कर सकता है।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

व्यंग्य

विदेशी कंपनियों का पूरा नियंत्रण

फिनटेक से संबंधित भारत के महत्त्वपूर्ण डेटा तक अमेरिकी कंपनियों की पैठ गहराती जा रही है। भारत के डिजिटल पेमेंट क्षेत्र पर वॉलमार्ट, गूगल, मेटा आदि जैसी विदेशी कंपनियों का लगभग पूरा नियंत्रण है।

फिनटेक ऐप क्रेड में 90 करोड़ डॉलर के निवेश और क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को ह्वाट्सऐप का वैश्विक प्रमुख बनाने के मेटा के फैसले से उचित ही भारतवासियों में उपलब्धि बोध भरा है। शाह अब अनेक बड़े नामों में शामिल हो गए हैं, जो भारत से शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। यह भारत की तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिभा तराशने की उच्च क्षमता की एक मिसाल है। मगर इस चकमते सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी हर उपलब्धि इस हकीकत को बेनकाब करती है कि भारत प्रतिभाओं का लॉन्च पैड बनने से आगे नहीं बढ़ पाया है।

स्वदेशी प्रतिभाएं भारत में स्टार्ट-अप्स के जरिए अपनी पहचान बनाती हैं, जिन्हें जल्द ही खासकर अमेरिकी कंपनियां खींच ले जाती हैं। नतीजतन, आज तक एक भी भारतीय ब्रांड अपनी अद्वितीय वैश्विक पहचान नहीं बना पाया है। क्रेड के सिलसिले में यह चिंताजनक पहलू भी उभरा है कि भारतीय फिनटेक में रणनीतिक निवेश के जरिए देश के महत्त्वपूर्ण डेटा तक अमेरिकी कंपनियों की पैठ गहराती जा रही है। भारत के डिजिटल पेमेंट क्षेत्र पर वॉलमार्ट, गूगल, मेटा आदि जैसी विदेशी कंपनियों का लगभग पूरा नियंत्रण है। 2018 में लॉन्च हुए क्रेड के आज लगभग एक करोड़ 70 लाख यूजर हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड, बीमा खरीदारी, यूपीआई पेमेंट, ऋण, निवेश आदि से जुड़े कार्य इस कार्ड से करते हैं।

ये भारत के सबसे समृद्ध उपभोक्ता हैं, जिनका बेहद अहम डेटा क्रेड के पास है। आशंका पैदा हुई है कि भविष्य में इस कंपनी अपना निवेश बढ़ाकर मेटा इन सारे आंकड़ों की मालिक बन सकती है। गौरतलब है कि ह्वाट्सऐप का इस्तेमाल भी पेमेंट ऐप के रूप में होता है। यह डेटा मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एजेंट के लिए भी बड़े काम का साबित हो सकता है। भारत में चीन की तरह डेटा ट्रांसफर पर रोक की कारगर कानूनी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संप्रभु एआई या संप्रभु हाई टेक का विकास की बातें खोखली नजर आने लगती हैं। इसीलिए क्रेड और मेटा में बना संबंध चिंता के पहलुओं को भी उजागर कर गया है।

ब्लॉग

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिरस्थाई विरासत: संस्थाएं, विचार और राष्ट्र निर्माण

गजेंद्र सिंह शेखावत

इतिहास अक्सर महान नेताओं को उनके राजनीतिक संघर्षों के जरिए याद करता है। लेकिन राजनेताओं के चिरस्मरणीय योगदान राजनीति के दायरे तक ही सीमित नहीं होते। उनकी वास्तविक विरासत उनके द्वारा सृजित संस्थाओं, परिपोषित विचारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े गए आदर्शों में होती है। राष्ट्र भारत केसरी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उनके सार्वजनिक जीवन के एक ऐसे पहलू को स्मरण करना प्रासंगिक होगा जिसकी ओर व्यापक रूप से गौर करने की जरूरत है। यह पहलू है, राष्ट्र निर्माण की बुनियाद के रूप में संस्थाओं का सृजन करने की उनकी आजीवन प्रतिबद्धता।

स्वतंत्र भारत का उदय सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष से नहीं हुआ। उसे विश्वविद्यालय बनाने थे जो नागरिकों को शिक्षित करने में सक्षम हों। ऐसी अनुसंधान संस्थाएं खड़ी करनी थीं जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार कर सकें। उसे ऐसे उद्योग तैयार करने थे जो आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा कर सकें। सभ्यता की विरासत की रक्षा करने वाले सांस्कृतिक संगठनों और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने वाली लोक संस्थाओं को तैयार करना था। डॉ मुखर्जी ने जल्दी ही समझ लिया था कि राष्ट्र का भविष्य सिर्फ दूरद्रष्टा नेतृत्व पर ही निर्भर नहीं करता। यह उन मजबूत संस्थाओं पर भी निर्भर करता है जो नेताओं और सरकारों से ज्यादा टिकाऊ होंगी।

उनका असाधारण शैक्षिक कॅरियर उनके विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने वैसे समय में यह कार्यभार संभाला जब उच्चतर शिक्षा भारत के बौद्धिक जागरण का केंद्र बन रही थी। उनके लिए विश्वविद्यालय सिर्फ स्नातक तैयार करने के स्थल नहीं थे। वे वैसे सुविज्ञ नागरिकों को गढ़ने वाले संस्थान थे जो सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ योगदान करने में सक्षम हों। उनकी राय थी कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के वृहत्तर कार्य से अलग नहीं किया जा सकता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के प्रति उनका समर्पण विश्वविद्यालयों के परिसर से कहीं आगे बढ़कर था। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु की कोर्ट और काउंसिल के सदस्य के तौर पर, उन्होंने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में से एक को मज़बूत बनाने में योगदान दिया। 1947 में, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ़ पावर इंजीनियरिंग की आधारशिला रखी क्योंकि वे भली-भांति समझते थे कि स्वतंत्र भारत की आर्थिक प्रगति के लिए

इंजीनियरिंग की शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षमता बहुत ज़रूरी होगी। नवाचार को मुख्य नीतिगत लक्ष्य बनाए जाने से बहुत पहले ही, उन्होंने यह समझ लिया था कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता और औद्योगिक विकास ही देश की दीर्घकालिक मज़बूती तय करेंगे।

स्वतंत्रता के बाद, जब डॉ. मुखर्जी भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, तब इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप दिया गया। उन शुरुआती सालों में, नए नए आज़ाद देश के सामने एक औद्योगिक आधार तैयार करने की बड़ी चुनौती थी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जैसे संस्थान सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के तौर पर नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प के प्रतीक के तौर पर स्थापित किए गए थे। डॉ. मुखर्जी के लिए, औद्योगीकरण कभी भी अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था; यह राष्ट्रीय क्षमता और सामूहिक आत्मविश्वास में किया गया एक निवेश था।

हालाँकि, किसी भी संस्थान के निर्माण के लिए केवल भौतिक अवसंरचना या प्रशासनिक कुशलता की ही ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए सहानुभूति, जन-सेवा और नैतिक ज़िम्मेदारी की भावना की भी आवश्यकता होती है। डॉ. मुखर्जी में इन गुणों की झलक 1943 के बंगाल अकाल के दौरान ही साफ़ तौर पर दिखाई दी थी, जब उन्होंने बीसवीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने में खुद को समर्पित कर दिया था। विभाजन के बाद, उन्होंने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। वे समझते थे कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में संस्थानों को फिर से खड़ा करने के साथ-साथ लोगों के दुख दर्द को कम करना और उस पर मरहम लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उनका सार्वजनिक जीवन, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी समझ और सम्मान को भी दर्शाता था। महाबोधि सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने बौद्ध देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई। सभ्यतागत कूटनीति के स्थायी महत्व को समझते हुए, बुद्ध के मुख्य शिष्यों—अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मौद्गल्यायन—के पवित्र अवशेषों का भारत में स्वागत करने में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आज भी, मंगोलिया जैसे देशों के साथ इन पवित्र अवशेषों को साझा करने की भारत की कोशिशें यह दिखाती हैं कि किस तरह सांस्कृतिक विरासत अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को मज़बूत करती है और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा बनाती है।

साहित्य और विद्वता के प्रति भी उनकी चिंता उतनी ही स्पष्ट थी। उनके पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने प्रसिद्ध कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम की उनके व्यक्तिगत संकट के समय किस तरह मदद की थी। ऐसी घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि सार्वजनिक नेतृत्व को केवल बड़े नीतिगत फैसलों से ही नहीं, बल्कि उदारता के उन शांत और मौन कार्यों से भी आंका जाता है, जिन पर शायद ही कभी लोगों का ध्यान जाता है।

डॉ. मुखर्जी ने संस्थागत निर्माण के इसी दृष्टिकोण को संविधान सभा में भी आगे बढ़ाया। संविधान के निर्माण को ₹एक बड़ी जिम्मेदारी₹ और ₹एक गंभीर और पवित्र विश्वास₹ के रूप में वर्णित करते हुए, उन्होंने संवैधानिक शासन के साथ जुड़ी नैतिक ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दिया। उनके वे शब्द आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। संविधान की ताकत अंततः न केवल उसके लिखित प्रावधानों पर, बल्कि संसद की शुचिता, सार्वजनिक संस्थानों की स्वतंत्रता, कानून के शासन और नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी निर्भर करती है। संवैधानिक लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब संस्थाओं पर जनता का भरोसा हो और वे ईमानदारी से काम करें।

जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, डॉ. मुखर्जी की सोच हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है। सिर्फ़ आर्थिक विकास से ही देश की तरक्की तय नहीं होती। संवहनीय विकास के लिए शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक संरक्षण और लोगों का भरोसा जगाने वाले संस्थानों में लगातार निवेश की ज़रूरत होती है।

सड़कें, हवाई अड्डे और कारखाने बेहद जरूरी हैं, लेकिन उतने ही जरूरी वे विश्वविद्यालय भी हैं जो जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हैं, वे प्रयोगशालाएँ जो ज्ञान का विस्तार करती हैं, वे संग्रहालय जो विरासत को संजोते हैं और वे सार्वजनिक संस्थान जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

संस्थाओं में एक अद्भुत गुण होता है: वे सरकारों, राजनीतिक आंदोलनों और यहाँ तक कि कई पीढ़ियों से भी ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं। वे संचित ज्ञान को संजोकर रखती हैं, बदलाव के बीच निरंतरता बनाए रखती हैं और समाज को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। नेता इतिहास को आकार दे सकते हैं, लेकिन संस्थाएं सभ्यता को जीवित रखती हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सार्वजनिक जीवन का सबसे अहम सबक यही है। उनकी विरासत केवल उन पदों तक सीमित नहीं है जो उन्होंने संभाले या उन बहसों में भी नहीं है जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि यह उनके उस अटूट विश्वास में निहित है कि मजबूत संस्थान ही किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं के सच्चे संरक्षक होते हैं।

जैसे-जैसे भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, ज्ञान, वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले संस्थानों को मजबूत करना ही उनके प्रति सबसे सार्थक श्रद्धांजलि होगी।

(लेखक केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं।)

राम मंदिर में एंट्री पर बड़ा बदलाव, अब महंत दीनेंद्र दास के आईडी से ही बनेंगे वीआईपी पास

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद जहां एक ओर मामले की जांच चल रही है तो वहीं मंदिर में अंदरुनी तौर पर काफी बदलाव किए जा रहे हैं। अहम बदलाव के तहत कल गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी निष्क्रिय कर दी ताकि ये लोग VIP पास जारी न कर सकें। अब महंत दिनेंद्र दास के पास VIP पास जारी करने की शक्ति आ गई है।

मंदिर में एंट्री को लेकर VIP पास जारी करने की शक्ति सिर्फ ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास के पास ही रहेगी। दीनेंद्र दास की आईडी को सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया गया है। अब इनके कहने पर ही सुगम और विशिष्ट

दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे। VIP दर्शन पास के लिए ट्रस्टी की शिफारिश जरूरी होती है।

चंपत-अनिल की आईडी डी-एक्टिवेट

ऐसे में अब ये जिम्मेदारी महंत दीनेंद्र दास को दी गई है। ट्रस्ट से छुट्टी होने के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी को डी-एक्टिवेट कर दिया गया। इन आईडी का इस्तेमाल वीआईपी दर्शन पास जारी करने में कथित अनियमितताओं को रोकने के उपायों के तहत किया गया। सूत्रों के अनुसार, तीनों लोगों के आईडी बंद करने का फैसला कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन की अगुवाई वाले नए मंदिर प्रशासन ने लिया। आईडी बंद होने से अब ये तीनों लोग किसी भी तरह से वीआईपी दर्शन पास जारी नहीं कर सकेंगे।

VIP पास बनाने ने खूब हुई धांधली

मंदिर प्रशासन की ओर से यह कदम राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही जांच के बीच उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई कि ट्रस्टियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की डिजिटल आईडी का बेहिसाब पास बनाने के लिए कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। मंदिर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन आईडी का इस्तेमाल उनकी सिफारिश पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। बड़ी संख्या में ऐसे पास बनाने के लिए रैकेट चलाने और कर कथित तौर पर लाखों रुपये कमाने के मामले की जांच हो रही है।

चंपत की जगह पूर्व IFS कृष्ण को कमान

सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक टिन्नू यादव ने इस खामी का फायदा उठाकर सैकड़ों अनधिकृत वीआईपी दर्शन पास बनाए। सूत्रों ने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के कुछ करीबी सहयोगी भी कथित तौर पर वीआईपी पास जारी करने के नाम पर रैकेट चलाने और अवैध रूप से लाखों रुपये कमाने के मामले में जांच की जा रही है। पिछले महीने जून के पहले हफ्ते में राम मंदिर में दान राशि की गिनती में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। चंदा चोरी के लिए विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। बढ़ते दबाव के बीच ट्रस्ट की सिफारिश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया।

पिछले दिनों चंपत राय के ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय वन सेवा (IFS) के पूर्व अधिकारी कृष्ण मोहन को उनकी जगह नियुक्त किया गया। जबकि ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को उनके पद से हटा दिया गया । हालांकि एफआईआर में इन तीनों में से किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया।

व्यापारियों के शोषण-उत्पीड़न का नया जरिया बना आईजीआरएस पोर्टल

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। लघु उद्योग व्यापार मंडल का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार का आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली), जिसे आम जनता शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बनाया गया था, अब कुछ मामलों में व्यापारियों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न का माध्यम बनता जा रहा है। संगठन का कहना है कि बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के दर्ज होने वाली शिकायतों के आधार पर अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण और नोटिस जारी किए जाने से ईमानदार व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। लघु उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी पी गुप्ता का कहना है कि कई शिकायतें व्यक्तिगत द्वेष, प्रतिस्पर्धा या दबाव बनाने की मंशा से दर्ज कराई जाती हैं। उनका आरोप है कि ऐसी शिकायतों की प्रारंभिक सत्यता की जांच किए बिना कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिससे व्यापारियों का समय, संसाधन और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और निवेश-अनुकूल वातावरण बनाने की बात कर रही है, लेकिन यदि शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो इससे व्यापारिक माहौल प्रभावित हो सकता है। लघु उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष प्रारंभिक जांच की जाए, दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायतों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो तथा बिना पर्याप्त आधार के व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उनका कहना है कि शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य न्याय दिलाना होना चाहिए, न कि उत्पीड़न का माध्यम बनना। व्यापारिक नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आईजीआरएस की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे द्वेषपूर्ण भावना से की गई शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण हो।

छात्रा हत्याकांड पर सियासत, वायरल ऑडियो के बाद एसएसपी का बड़ा बयान, बोले- मेरे विरोधी दो पेड़ लगाएं

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में अनुसूचित जाति की छात्रा हत्याकांड को लेकरसियासी माहौल लगातार गरमा रहा है। मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में तैनात कांस्टेबल भाई अंकित को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक नगर विनायक गोपाल भोसले को सौंपी गई है। दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता को थप्पड़ मारने के विवाद और उसके बाद मिली कथित धमकियों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी आज पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचेंगे। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

धमकी भरे ऑडियो पर एसएसपी का सख्त संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने सामाजिक माध्यम पर मिल रही धमकियों और हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ की गई है और प्रत्येक कार्रवाई के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है, इसलिए किसी भी जाति, दल या समुदाय के नाम पर माहौल बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर भ्रामक बयान देने वाले लोगों के संबंध में भी पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि जो लोग पुलिस की वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वृक्षारोपण का भी किया आह्वान

एसएसपी ने अपने समर्थकों से आगामी वृक्षारोपण महोत्सव में एक पौधा लगाने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो मेरे पक्ष में है वे एक पौधा लगाएं और जो मेरे विरोध करने वाले लोगों हैं, वे दो पौधे लगाकर अपना गुस्सा शांत करें। समाज में सकारात्मक संदेश देना सभी की जिम्मेदारी है।

आरोपी का पीएसी कांस्टेबल भाई निलंबित

हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के भाई अंकित, जो 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक नगर विनायक गोपाल भोसले को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आज मेरठ आएंगे चंद्रशेखर आजाद

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज रोहटा क्षेत्र स्थित गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सामाजिक माध्यम पर इसकी जानकारी देते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता अपना जवाब देगी। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है।

बेहतर अध्ययन से भविष्य का निर्माण संभव : कुलपति

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा गोद लिए गए ग्रामों के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु दीक्षांत समारोह से जुड़े कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित एकलव्य स्टेडियम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना भवन में किया गया। कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी और राष्ट्रनिर्माता बनेंगे।कुलपति ने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि जो भी विषय पढ़ें, उसे केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करें। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ संतुलित आहार भी अत्यंत आवश्यक है।

हाईवे पर भरा पानी, बिजनौर का मेरठ-मुजफ्फरनगर से सीधा संपर्क टूटा... डायवर्जन से 125 KM घूमकर जाने पर मजबूर लोग

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे-34 (NH-34) पर भारी जलभराव और सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बिजनौर का मेरठ और मुजफ्फरनगर से सीधा सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र के देवल गांव के पास सर्विस रोड पर करीब तीन से चार फीट तक पानी भर गया है।

इससे प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके चलते दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को लगभग 125 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्गों से होकर निकाला जा रहा है।

हाईवे बना समंदर, वाहनों की कतारें

पिछले दो दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते एनएच-34 पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देवल गांव में हाईवे

निर्माणाधीन होने के कारण वन निगम डिपो के सामने की चट्टान से भारी मात्रा में कच्ची मिट्टी बहकर सड़क पर आ गई है। इसके साथ ही सर्विस रोड पर चार फीट से अधिक पानी भर जाने की वजह से गुरुवार दोपहर से ही बिजनौर गंगा बैराज से लेकर मीरापुर तक वाहनों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। हादसों की आशंका को देखते हुए बिजनौर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रूट को पूरी तरह डायवर्ट कर दिया है।

125 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करने को मजबूर हुए लोग

यातायात पुलिस बिजनौर के निर्देशानुसार, बिजनौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की ओर जाने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों को अब चांदपुर-धनौरा-गजरौला मार्ग से होकर भेजा जा रहा है। कुछ वाहनों को अमरोहा और चांदपुर के दतियाना पुल से हस्तिनापुर होते हुए निकाला जा रहा है। इस डायवर्जन के कारण वाहन चालकों को करीब 125 किलोमीटर से अधिक दूरी का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएआई (NHAI) के एसडीओ आशीष शर्मा के अनुसार, हाईवे का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। बारिश के अत्यधिक पानी के कारण किनारों पर डाली गई कच्ची मिट्टी बहकर सड़क पर आ गई है, जिसे दुरुस्त करने और किनारों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है।

हत्याकांड में एक लाख के इनामी का सरेंडर

जौनपुर। जिले के बहुचर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लंबे समय से फरार चल रहा और एक लाख रुपये का इनामी मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। ज्ञात हो कि 1 मई को खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव के पास बारात लेकर जा रहे दूल्हा आजाद बिंद की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी और शादी का माहौल पलभर में मातम में बदल गया था। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और कई टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया।जांच के दौरान तीन मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए। इनमें एक लाख रुपये का इनामी रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि एक अन्य एक लाख का इनामी भोले राजभर कुछ दिन पहले अदालत में आत्मसमर्पण कर चुका है।

विवाहिता की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के लक्षनपुर गांव में बृहस्पतिवार रात को विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत।मृतका की मा किशुना देवी पत्नी शोभनाथ ने लिखित तहरीर देकर दहेज न देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है।पुलिस शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। पुलिस के अनुसार, लक्षनपुर गांव की 24 वर्षीय विवाहिता शांति गौड़ पत्नी अमन गौड़ की मौत हो गई।वही मृतका की छोटी बहन सरिता का आरोप है कि बड़ी बहन शांति देवी की शादी 22अप्रैल 2023 मे अमन गौड़ से हुई थी कुछ दिनों बाद से ही दहेज के लिए बहन शांति देवी को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ति करना और आए दिन मारना पीटना शुरू कर दिए,जिसके लिए कई बार पंचायत भी हुई लेकिन सुधार नहीं हुआ।बृहस्पतिवार रात 11 बजे बहन शांति ने फोन किया था वह पूरी तरह घबराई हुई थी उसने कहा सरिता ये लोग दौड़ा दौड़ाकर मारपीट रहे है आज मुझे जान से मार देंगे इतने में जीजा अमन ने फोन छीनकर फोन काट दिया सरिता ने बताया कि मैं बार बार फोन किया लेकिन मोबाइल फोन बंद आने लगा।शुक्रवार भोर करीब 3 बजे भोर में दीदी की ननद अनीता ने फोन करके बताया कि तुम्हारी दीदी शांती देवी ने घर के बगल एक अमरूद के पेड़ में साड़ी के फंदे बनाकर फंदे से झूलकर जान दे दी। बस इसी सूचना पर जब छोटी बहन सरिता और मां किशुना देवी मौके पर पहुंची तो शांति देवी का शव जमीन पर पड़ा था। मृतिका एक बच्ची की माँ हैजो एक वर्ष की है।सरिता ने घटना की सूचना 112 और नेवढ़िया पुलिस को दिया।सूचना पाके मौके पर नेवढ़िया थानाध्यक्ष पुलिस के पहुंचने पर भी शव जमीन पर पड़ी थी।ससुराल पक्ष फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात बता रहे थे।वही मायके पक्ष की मां किशुना देवी ने लिखित तहरीर देकर ससुराल पक्ष के पति अमन गौड़, जेठ पिंटू गौड़, जेठान संगीता, सास बेला देवी,ननद अनीता पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है।घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी मडियाहूं विजय कुमार चैधरी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की ।

क्रिकेट मैच देख रहे मासूम ने कहा- ये नो बॉल नहीं... क्लीन बोल्ड हुए खिलाड़ी ने बैट से कर दिया हमला, मौत

आर्यावर्त संवाददाता

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से खेल के मैदान को कलंकित करने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक क्रिकेट मैच के दौरान महज नो बॉल के विवाद को लेकर 12 वर्षीय किशोर की क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच का साथ देते हुए विवादित गेंद को नो बॉल मानने से इनकार कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल बच्चे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

ये दर्दनाक घटना भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भानीपुर गांव की है। भानीपुर गांव का रहने वाला 12 वर्षीय आदित्य कुमार बुधवार शाम करीब 4 बजे अपने घर से महज 200 मीटर दूर स्थित अंबेडकर पार्क में चल रहा क्रिकेट मैच देखने गया था। वो खुद खेल में शामिल नहीं था, बल्कि मैदान के किनारे बैठकर अन्य बच्चों का मैच देख रहा था। शाम करीब 5 बजे मैच के दौरान बल्लेबाजी कर रहा 15 वर्षीय एक किशोर एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया। आउट होने के बावजूद उसने खुद को आउट मानने से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि वह गेंद नो बॉल थी। इस बात को लेकर खेल रहे बच्चों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

क्रिकेट बैट से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार

विवाद को सुलझाने के लिए मैदान पर खेल रहे लड़कों ने बाहर बैठे आदित्य से उसकी राय पूछी। निष्पक्ष होकर आदित्य ने सीधे कह दिया कि 'गेंद नो बॉल नहीं है।' आदित्य के मुंह से यह सच सुनते ही आरोपी बल्लेबाज गुस्से से आगबबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव, अपने हाथ में पकड़े क्रिकेट बैट से आदित्य के सिर पर एक के बाद एक कई जोरदार वार कर दिए। सिर फटने के कारण आदित्य खून से लथपथ होकर वहीं मैदान पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

गवाह को दी जान से मारने की धमकी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने वहां मौजूद आदित्य के चचेरे भाई को भी गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसने घर जाकर इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे भी जान से मार देगा। हालांकि, चचेरे भाई ने किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई।

तीन बहनों का इकलौता भाई था मासूम

घटना की जानकारी मिलते ही आदित्य के पिता संजय कुमार और अन्य परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। परिजन तुरंत खून से लथपथ आदित्य को लेकर सुरियावां स्थित संगम अस्पताल भागे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उसे भदोही शहर के जीवनदीप अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार रात 8:28 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उजड़ गए परिवार के सपने

इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। संजय कुमार मुंबई में मेहनत-मजूदरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। चार बच्चों में आदित्य उनका इकलौता बेटा था और उसकी एक बड़ी व तीन छोटी बहनें हैं। आदित्य पढ़ाई में बेहद होनहार था और इसी साल उसने कक्षा छह में दाखिला लिया था। सबसे दुखद बात यह है कि पूरा परिवार गुरुवार को काशी एक्सप्रेस से मुंबई जाने वाला था, जिसके टिकट भी बुक हो चुके थे। परिवार वहां एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही यह भयावह हादसा हो गया।

पुलिस की कार्रवाई: आरोपी हिरासत में, जांच जारी

दुर्गागंज थाना पुलिस ने पीड़ित पिता के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या की सुसंगत धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 वर्षीय आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की कानूनी तफ्तीश को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा में पहली ही बारिश में उखड़ा नया रेलवे ओवर ब्रिज, 15 दिन पहले हुआ था 858 करोड़ के इस पुल का उद्घाटन

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। यूपी के हाईटेक शहर कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा में बनाया गया रेलवे ओवर ब्रिज पहले ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गया। 15 दिन पहले 858 करोड़ के इस पुल का उद्घाटन हुआ था और लोगों के लिए इसे खोला गया था। इस ओवर ब्रिज की सड़क जगह-जगह उखड़ गई है। लगभग 100 मीटर लंबे हिस्से में सड़क टूटने और कंक्रीट उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले दो-तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच फ्लाइओवर की सड़क कई स्थान पर टूट गई है और कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ कर बाहर आ गई है।

शहर के लोगों का कहना है कि

जिस ओवर ब्रिज को शहर की बड़ी परियोजनाओं में गिना जा रहा था। वह मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। जिससे फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद डीएफसीसीएल ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले एक से दो दिनों के भीतर पूरी सड़क की मरम्मत कर ट्रैफिक के लिए सुरक्षित बना दिया जाएगा।

लंबे इंतजार के बाद मिला था ओवर ब्रिज

130 मीटर रोड पर बने इस रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण लंबे समय से चल रहा था। निर्माण पूरा होने के बाद दो तीन चरणों में तकनीकी निरीक्षण किया गया और लगभग एक महीने पहले इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इतनी जल्दी सड़क का उखड़ जाना निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

शहर के लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने फ्लावर की सड़क यदि पहली ही बारिश में टूट जाए तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि केवल मरम्मत कर देना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर निर्माण में ऐसी कौन सी कमी रही, जिसके कारण नया फ्लाइओवर पहली बारिश का सामना भी नहीं कर पाया। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है की मरम्मत के बाद सड़क कितनी टिकाऊ साबित होती है और संबंधित एजेंसी गुणवत्ता को लेकर क्या कार्रवाई करती है।

बारिश और जलजमाव आपके लिवर के लिए न बढ़ा दे खतरा? डॉक्टरों की चेतावनी पर गंभीरता से दें ध्यान

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव और गंदे पानी ने नई स्वास्थ्य चिंता भी खड़ी कर दी है। इनमें सबसे बड़ा खतरा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का माना जाता है, जो सीधे लिवर पर हमला करने वाले वायरल संक्रमण हैं।

राजधानी दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कई इलाकों में 100 मिमी से अधिक बारिश होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार शाम से जारी लगातार बारिश के कारण गुरुवार सुबह लोगों को अपने काम पर जाने के लिए खासा मुश्किलों के सामना करना पड़ा। जगह-जगह पर जलभराव की स्थिति न सिर्फ यातायात व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, साथ ही गंदे पानी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को अलर्ट करते हुए सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के साथ वायरल संक्रमण का खतरा तो रहता ही है साथ ही बारिश के कारण ओवरफ्लो सीवर और जलजमाव ने लिवर फेल करने वाले संक्रमण का खतरा भी बढ़ा दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रभावित इलाकों में सभी लोगों को हेपेटाइटिस-ए और हेपेटाइटिस-ई जैसे संक्रमण को लेकर गंभीरता से सावधानी बरतनी चाहिए।

हेपेटाइटिस-ए और ई का खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार, हेपेटाइटिस-ए और ई, मुख्य रूप से दूषित पानी और संक्रमित भोजन के जरिए फैलते हैं। बारिश के मौसम में जब सीवर का पानी पेयजल के स्रोतों में मिल जाता है तो इससे इन संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये संक्रमण लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा मानसून के इस मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को लेकर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर सीवर ओवर फ्लो है या जलजमाव की स्थिति है तो खान-पान को लेकर बहुत सावधानी जरूरी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दूषित पानी और खराब स्वच्छता के कारण हेपेटाइटिस ए और ई सहित कई संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। जलजमाव के कारण नल के पानी में सीवेज का रिसाव भी हो सकता है, जिससे संक्रमण का जोखिम और बढ़ जाता है। मानसून के दौरान जलजनित और खाद्यजनित संक्रमणों के मामले हर साल बढ़ते हैं।

पहले हेपेटाइटिस -ए के बारे में जानिए

हेपेटाइटिस ए एक वायरल लिवर संक्रमण है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के जरिए फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति के मल (सीवर का पानी) से पानी या भोजन दूषित हो जाता है और दूसरा व्यक्ति उसका सेवन करता है, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर लिवर को संक्रमित कर देता है। इसलिए इसे फीकल-ओरल ट्रांसमिशन कहा जाता है। गंभीर स्थितियों में इससे लिवर फेलियर हो सकता है।

हेपेटाइटिस ई का भी खतरा

हेपेटाइटिस-ई भी एक वायरल लिवर संक्रमण है। इसके फैलने का तरीका भी लगभग हेपेटाइटिस-ए जैसा ही होता है। यह दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलता है और स्वच्छता की कमी वाले जगहों पर इसके मामले अधिक देखे जाते हैं।

हेपेटाइटिस-ई के कारण भी बुखार-कमजोरी, मतली-उल्टी, पेट दर्द और पीलिया जैसी दिक्कतें होती हैं। गहरे रंग का पेशाब और अत्यधिक थकान शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं में यह संक्रमण बहुत गंभीर रूप ले सकता है।

बारिश के दिनों में लिवर संक्रमण का खतरा

हेपेटाइटिस ए और ई दोनों ही दूषित भोजन या पानी से फैलते हैं लिवर में गंभीर सूजन से लेकर फेलियर तक का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिस ई जूनोटिक भी होता है और ये अधपके मांस से फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बारिश के मौसम में हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय करें।

केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। भोजन हमेशा ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाएं।

सड़क किनारे खुले में रखे कटे फल, चाट या अन्य खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि ये दूषित हो सकते हैं।

खाना बनाने और खाने से पहले तथा शौचके बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना संक्रमण रोकने का सबसे आसान और प्रभावी उपाय है।

यदि किसी इलाके में जलजमाव है, तो वहां के पानी के संपर्क में आने के बाद हाथ-पैर अच्छी तरह साफ करें।

कर्ली बालों की देखभाल के लिए खरीदते हैं प्रोडक्ट्स? इन 5 बातों का रखें ध्यान

कर्ली बालों की देखभाल के लिए खास ध्यान देने की जरूरत होती है। जब आप कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और सुंदर दिखें। सही प्रोडक्ट्स का चयन करने से न केवल आपके बाल मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी चमक भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कि कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्राकृतिक चीजों का चयन करें

जब भी आप कर्ली बालों के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें प्राकृतिक चीजें होनी चाहिए। हर्बल और प्राकृतिक सामग्रियां बालों को पोषण देती हैं और उन्हें स्वस्थ रखती हैं।

केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स से बचें क्योंकि ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी चमक को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक चीजों वाले प्रोडक्ट्स आपके बालों को नमी प्रदान करते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।

नमी बहुत जरूरी है

कर्ली बालों को नमी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शैंपू और कंडीशनर चुनें, जो आपके बालों को गहराई से नमी दें। बिना सल्फेट और पैराबेन वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें ताकि आपके बाल मुलायम और चमकदार रहें। इसके अलावा नमी बनाए रखने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार हेयर मास्क का उपयोग करें। यह आपके बालों को पोषण देगा और उन्हें टूटने से बचाएगा।

हल्के तेलों का करें इस्तेमाल

हल्के तेल जैसे नारियल तेल या जोजोबा तेल आपके कर्ली बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तेल बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। रात को सोने से पहले इन तेलों की मालिश करें और सुबह धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार रहेंगे। इसके अलावा इन तेलों का नियमित उपयोग बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है।

सुलझाने के लिए सही ब्रश का उपयोग

कर्ली बालों को सुलझाने के लिए सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। डिटैंगलिंग ब्रश या वाइड टूथ कॉम्ब आपके बालों को बिना टूटे सुलझा सकता है। गीले बालों पर हल्के हाथों से उपयोग करें ताकि बाल कमजोर न हों। इसके अलावा बालों को सुलझाने से पहले थोड़ा सा कंडीशनर लगाएं, इससे बाल आसानी से सुलझेंगे और उनकी चमक भी बढ़ेगी। नियमित उपयोग से आपके बाल मुलायम और स्वस्थ रहेंगे।

गर्मी से बचाव करें

गर्मी आपके कर्ली बालों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है। हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर का उपयोग करने से बचें क्योंकि ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको बालों को सेट करना है तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाएं ताकि बाल सुरक्षित रहें। इसके अलावा गर्मी वाले उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और प्राकृतिक तरीकों से अपने बालों को सुखाने की कोशिश करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और

मानसून में वॉशिंग मशीन का ऐसे रखें ध्यान, कपड़ों में नहीं आएगी सीलन की बदबू

बरसात के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसका असर वॉशिंग मशीन पर भी पड़ता है। धुलाई के बाद मशीन के अंदर बची नमी जल्दी नहीं सूखती और लंबे समय तक बनी रहती है। इससे ड्रम, रबर सील और डिटर्जेंट ट्रे में फफूंदी, बैक्टीरिया और बदबू बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसका असर मशीन के साथ-साथ कपड़ों की सफाई और उनकी खुशबू पर साफ दिखाई देने लगता है।

धुलाई के बाद यह काम जरूर करें

विशेषज्ञों की सलाह है कि हर धुलाई के बाद वॉशिंग मशीन का दरवाजा और डिटर्जेंट ट्रे कुछ घंटों के लिए खुली छोड़ दें। इससे अंदर की नमी आसानी से बाहर निकल जाती है और हवा का प्रवाह बना रहता है। दरवाजा बंद करने से पहले रबर की सील को सूखे और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। टॉप-लोड मशीन इस्तेमाल करने वाले लोग भी धुलाई के बाद कुछ समय तक ढक्कन खुला रखें।

समय-समय पर करें मशीन की सफाई

हर दो से तीन सप्ताह में बिना कपड़ों के गर्म पानी के साथ वॉशिंग मशीन क्लीनर चलाना फायदेमंद माना जाता है। इससे अंदर जमी गंदगी, फफूंदी और बैक्टीरिया साफ होने में मदद मिलती है। मशीन को हमेशा हवादार जगह पर रखें और ऐसी जगह लगाने से बचें, जहां सीधे बारिश या अधिक नमी का असर पड़ता हो। इससे वॉशिंग मशीन काफी लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनी रहती है।

इन छोटी सावधानियों से बचेंगे बड़े खर्च से

वॉशिंग मशीन के बिजली कनेक्शन, पावर सॉकेट और अर्थिंग की समय-समय पर जांच कराते रहें, ताकि नमी से होने वाली खराबी से बचा जा सके। अगर मशीन से बदबू आने लगे, पानी ठीक से बाहर न निकले या कोई दूसरी समस्या दिखे तो तुरंत जांच कराएं। समय पर सर्विस कराने से छोटी खराबी बड़ी नहीं बनती और मशीन की कार्यक्षमता तथा उम्र दोनों लंबे समय तक बेहतर बनी रहती हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीमित, भारत की आर्थिक नींव मजबूतः आईएमएफ

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक संस्था ने भारत की 2026 की ग्रोथ का अनुमान थोड़ा घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगले साल ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतों के कम होने पर देश की ग्रोथ और तेज होगी।

आईएमएफ ने अपने ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान अप्रैल के अनुमान से 0.1 प्रतिशत अंक घटा दिया, लेकिन 2027 के लिए अनुमान 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया। आईएमएफ का कहना है कि उम्मीद से बेहतर आर्थिक गतिविधि और मजबूत घरेलू मांग देश के आउटलुक को सहारा दे रही है।

आईएमएफ अधिकारियों ने अपनी ताजा 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भारत ने कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ग्लोबल अनिश्चितता का बेहतर ढंग से सामना किया है, हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव की वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस साल विकास दर पर असर डालेंगी।

आईएमएफ रिसर्च विभाग की प्रमुख डेनिज इगन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया, भारत के लिए, हमने इस साल के अनुमान को बहुत मामूली रूप से 0.1 प्रतिशत अंक घटाकर 6.4 कर दिया है। और अगले साल, यानी 2027 के लिए विकास दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है।

इगन ने कहा, अच्छी बात यह है कि हाल के डेटा में नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। साथ ही, अप्रैल तक के हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी दिखाते हैं कि कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में काफी मजबूती बनी हुई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस साल ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने इस सकारात्मक गति के असर को खत्म कर दिया है। हालांकि,आईएफएफ को उम्मीद है कि अगले साल ये दबाव कम हो जाएंगे।

इगन ने कहा, 2027 की ओर बढ़ते हुए, हमें उम्मीद है कि भारत की ग्रोथ और मजबूत होगी क्योंकि एनर्जी शॉक का असर कम हो जाएगा और मीडियम-टर्म ग्रोथ लगभग 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भारत के लिए यह नया अनुमान तब आया है जब आईएमएफ ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 3 प्रतिशत और 2027 के लिए 3.4 प्रतिशत पर लगभग वैसा ही बनाए रखा है।

आईएमएफ का कहना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ने अब तक मिडिल ईस्ट के संघर्ष का सामना शुरुआती आशंकाओं से बेहतर तरीके से किया है।

इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने 2026 के लिए ग्लोबल हेडलाइन महंगाई का अनुमान भी बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया है। उसका कहना है कि 2024 की शुरुआत से चल रहा महंगाई कम होने का ट्रेंड रुक गया है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रहा इन्वेस्टमेंट एनर्जी की ऊंची कीमतों से हुए कुछ आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में मदद कर रहा है, जिससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन से जुड़े देशों को फायदा हो रहा है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ग्लोबल एनर्जी की कीमतें महंगाई, चालू खाते और कुल आर्थिक ग्रोथ पर असर डालने वाला एक अहम फैक्टर हैं। होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई में लंबे समय तक कोई रुकावट आने पर भारत के लिए आयात की लागत बढ़ सकती है और घरेलू ईंधन की कीमतों पर फिर से दबाव पड़ सकता है।

बिना एक रुपया खर्च किए जेब में पड़ी है 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। मौजूदा समय में हर कोई अपने और परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को बेहद जरूरी मानता है और इसके लिए हर साल मोटी रकम भी खर्च करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में एक ऐसी मुफ्त इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ी है, जिसके लिए आपको एक चवन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ती? जी हां, आपके बैंक का एटीएम (या डेबिट कार्ड सिर्फ पैसे निकालने या ऑनलाइन शॉपिंग के ही काम नहीं आता, बल्कि यह खुद में एक चलता-फिरता 5 लाख रुपये तक का मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। जानकारी के अभाव में देश के ज्यादातर लोग कभी इस सुविधा का लाभ या क्लेम नहीं ले पाते हैं।

हर बैंक के एटीएम कार्ड पर मिलती है मुफ्त बीमा की सुविधा

भारत में चाहे कोई सरकारी बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट बैंक, अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी करते समय वे इसके साथ मुफ्त एक्सीडेंटल पॉलिसी की सुविधा भी देते हैं। नियम के मुताबिक, यदि किसी एटीएम कार्ड धारक के साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी हो जाती है, तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा सीधे उसके परिवार या नॉमिनी को मिलता है। चूंकि बैंक इस पॉलिसी के बारे में ग्राहकों को अलग से ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए मुश्किल वक्त में परिवार इस आर्थिक मदद और अधिकार से पूरी तरह वंचित रह जाता है।

कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से तय होती है बीमे की रकम

बैंकों द्वारा एटीएम और डेबिट कार्ड की अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार ही मुफ्त इंश्योरेंस की राशि तय की जाती है। साधारण या क्लासिक और रुपे कार्ड धारकों को 1 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। वहीं, प्लेटिनम कार्ड धारकों के लिए यह राशि 2 लाख रुपये होती है, जबकि प्रीमियम या वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को पूरे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है।

क्लेम पाने के लिए कार्ड का 'एक्टिव' होना है सबसे जरूरी शर्त

इस मुफ्त इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए बैंक की एक बेहद छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है, जिसे 'एक्टिविटी पीरियड' कहा जाता है। नियम के तहत बीमा क्लेम करने के लिए आपका एटीएम कार्ड पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति से पिछले 30 से 90 दिनों के भीतर उस एटीएम कार्ड से कम से कम एक बार कोई भी लेनदेन (ट्रांजैक्शन) जरूर किया गया हो। यदि कार्ड का इस्तेमाल नियमित रूप से हो रहा है, तभी इसे एक्टिव माना जाएगा और क्लेम का फायदा मिलेगा।

परिवार ऐसे कर सकता है इंश्योरेंस राशि के लिए क्लेम

दुर्घटना की स्थिति में क्लेम पाने के लिए कार्ड धारक के परिवार या नॉमिनी को सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा को इस घटना की सूचना देनी होती है। इसके बाद बैंक से मिलने वाले एक क्लेम फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों, जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस एफआईआर की कॉपी के साथ जमा करना होता है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद बैंक द्वारा खाते में दर्ज नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम जारी कर दी जाती है।

उज्बेकिस्तान में केरल की मेडिकल छात्रा की बेरहमी से हत्या

उज्बेकिस्तान। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना लेकर गई केरल की एक होनहार बेटी की उज्बेकिस्तान में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उज्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस (MBBS) प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही 22 वर्षीय छात्रा सावरिया बसंत की उसके ही सहपाठी ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उज्बेक जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपी द्वारा मृतका पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता के शव को केरल लाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने मृतका के माता-पिता की शिकायत पर हत्या का जीरो FIR मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरी दर्दनाक घटना उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर की है, जहां केरल और देश के अन्य हिस्सों से कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। केरल के अलाप्पुझा जिले के हरिपाद की रहने वाली सावरिया बसंत (22) और केरल के ही मलप्पुरम जिले का रहने वाला सदरुल अनम (22) दोनों बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में सहपाठी थे। 23 जुलाई को कॉलेज परिसर में किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। गुस्से में आगबबूला होकर आरोपी सदरुल अनम ने सावरिया पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने सावरिया के सिर पर भारी-भरकम लैपटॉप से कई वार किए। उज्बेक पुलिस की जांच में कई चश्मदीद छात्रों ने बयान दिया है कि उन्होंने संदिग्ध आरोपी सदरुल को घटना से पहले छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते और प्रताड़ित करते हुए देखा था। मृतका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे साफ है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। घटना की सूचना मिलते ही बदहवास माता-पिता तुरंत उज्बेकिस्तान पहुंचे और वहां की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बेटी के शव को अपने गृह नगर हरिपाद लेकर आए।

इजराइल ने अमेरिका को बताई वो खुफिया रिपोर्ट, जिससे ईरान पर और भड़क सकते हैं ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान-अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर है। समझौता टूट गया है। ईरान ने पहले 07 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसाए। इसके बाद लगातार दोनों देशों के बीच हमले जारी है। इस बीच इजरायल ने अमेरिका के साथ एक ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है, जो इस जंग को और भी खतरनाक स्तर तक भड़का सकता है।

CNN के मुताबिक उन्हें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि इज़राइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई योजना बनाई है। यह चेतावनी इस हफ्ते मिली। वहीं, CNN के दूसरे सूत्र ने बताया कि ट्रंप की हत्या की संभावित योजनाओं के बारे में अमेरिका को लगातार खुफिया जानकारी मिल रही थी। लेकिन इजरायल की चेतावनी नई और बड़ी थी।

हालांकि, कई अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल की यह रिपोर्ट ट्रंप के फ़ैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। दरअसल, ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को तेज करने पर विचार कर रहे हैं। इजराइल की यह रिपोर्ट इस फैसले पर मुहर लगवाने में अहम साबित हो सकती है। हालांकि, अब तक आधिकारिक तौर पर न तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है और न ही इजरायल ने।

ट्रंप के बयान क्या इशारा कर रहे हैं?

अमेरिकी सरकार लंबे समय से चेतावनी देती रही है कि ईरान 2020 में ट्रंप के आदेश पर किए गए ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसमें ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। हाल में ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं। बुधवार यानी 08 जुलाई को मीडिया से बातचतीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि 'वे अमेरिकी नेता , यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं।'

ट्रंप ने आगे कहा था कि 'मैं किसी न किसी सूची में हूं। मैंने आज सुबह देखा कि मैं उनकी हर सूची में हूं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूं। लेकिन शायद यह ज़्यादा समय तक न चले। ये बुरे, बीमार लोग हैं। हमें उस कैंसर को जड़ से खत्म करना होगा। क्या आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं? आपको कैंसर को शुरुआती चरण में ही काटकर हटाना होता है। मैं ऐसा ही महसूस करता हूं।

ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें हाल ही में एक नई सूची के बारे में पता चला है। ईरान की हत्या को लेकर मुख्य लक्ष्य बताया गया है। हालांकि, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं कि वे इजरायल से मिली खुफिया जानकारी का जिक्र कर रहे थे या नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चिंता है कि ईरान कई मौजूदा और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बना सकता है। हालांकि, इजरायली रिपोर्ट को ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने का जरिया माना जा रहा है, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के खिलाफ थे।

खामेनेई के जनाजे में ट्रंप की मौत की मांग उठी थी

फिलहाल, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को मशहद में 9 जुलाई को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। उनके जनाजे के दौरान ईरानियों की भीड़ ने ट्रंप की मौत की मांग की।खामेनेई युद्ध की शुरुआत में ही 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में मारे गए थे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। 60 दिन का सीज़फायर भी टूट गया है।

खामेनेई के जनाजे में खूब भीड़ जुटी लेकिन ईरान के बड़े नेता रहे गायब, पूर्व राष्ट्रपति और मुज्तबा भी नहीं दिखे

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई विदाई दे दी है। खामेनेई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजरायली एयरस्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी। खामेनेई के जनाजे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे मुज्तबा की गैरमौजूदगी की हुई। हालांकि, उनके परिवार के अन्य सदस्य उनके जनाजे में जरूर शामिल हुए। CNN के मुताबिक मुज्तबा सुरक्षा कारणों से जनाजे में शामिल नहीं हुए। लेकिन जनाजे की लाखों लोगों की भीड़ के बीच ईरान के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों की गैरमौजूदगी ने देश के राजनीतिक भविष्य और एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करने के दौरान कई पूर्व

राष्ट्रपति नजर नहीं आए। इसमें सुधारवादी नेता मोहम्मद खातमी और हसन रूहानी शामिल हैं। इनके साथ खामेनेई के लंबे समय से मतभेद रहे थे।

पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम के दौरान नदारद रहे। उनके भी संबंध पूर्व सुप्रीम लीडर के साथ खराब हो गए थे। हालांकि, सोमवार यानी 06 जुलाई को वह खामेनेई को दी जा रही अंतिम विदाई के जुलूस में जरूर दिखाई दिए। सालों तक राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहने के बाद वह इस तरह सार्वजनिक तौर पर नजर आए।

खामेनेई की अंतिम विदाई में इन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने ईरान की राजनीतिक एकजुटता की छवि पर नए सवाल खड़े कर दिए, जिसे ईरानी अधिकारी पेश करना चाहते थे। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है ईरानी अधिकारियों ने जानबूझकर भागीदारी को केवल मौजूदा नेतृत्व के करीबी लोगों तक ही सीमित रखा।

ईरानी नेतृत्व के पास राजनीतिक एकजुटता दिखाने का था शानदार मौका

अमेरिका स्थित ईरान विशेषज्ञ और 'व्हाट ईरानियंस वांट' के लेखक अराश अजीज़ी ने कहा कि आयोजक सुधारवादी राजनीति से जुड़े पूर्व राष्ट्रपतियों को खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल कर राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कार्यक्रम में सिर्फ शासन के मुख्य और शीर्ष अधिकारियों को ही शामिल करने का फैसला किया।

खामेनेई के जनाजे कार्यक्रम से ईरान यह संदेश देना चाहता था

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाएज़ ने बताया कि तेहरान अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बाद भी यह दिखाना चाहता था कि उसका सिस्टम लगातार काम करता रहेगा। वह शासन की निरंतरता बनाए रख सकता है। भारी भीड़ और सोच-समझकर आयोजित किए गए अंतिम विदाई कार्यक्रम इसकी ओर इशारा भी करते हैं। लेकिन कार्यक्रम से देश की बड़ी गैर-मौजूदगी दुनिया को यह भी बताती है कि उनका नेतृत्व अभी भी खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं कर रहा है।

मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान के बीच गोलीबारी तेज, सीजफायर डील पर खतरा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने कई जगहों पर धमाकों की खबर दी, जिनमें बुशहर (जहां ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स है) और दक्षिणी बंदरगाह शहर शामिल हैं। बुशहर के स्थानीय अधिकारी एहसान जहानियन के हवाले से कहा कि अमेरिका ने दोपहर के आसपास प्लांट के पास हमला किया। इसके जवाब में तेहरान ने अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों को निशाना बनाया।

इस गोलीबारी से उस अंतरिम समझौते पर खतरा पैदा हो गया है, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करना था। एक दिन पहले हुए हमलों समेत, लगातार हो रहे हमलों से सीजफायर को बार-बार खतरा पैदा हुआ है। लेकिन गुरुवार को हुए हमले ज़्यादा बड़े लग रहे थे। बहरीन में, जहां अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, कम से कम तीन बार सायरन बजे, और कुवैत व कतर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया।

गुरुवार दोपहर जॉर्डन में भी सायरन बजे, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक और विमान तैनात कर रखे हैं। ईरान के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि गुरुवार को बाद में अमेरिका ने ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आस-पास के इलाके को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। दोपहर के समय देश के अन्य हिस्सों में भी धमाकों की खबरें आईं। शुक्रवार तड़के, कई दिनों के सार्वजनिक शोक के बाद, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। ईरान युद्ध की शुरुआती गोलाबारी में खामेनेई मारे गए थे।

ये हमले तब हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हालिया ईरानी हमलों से नाजुक युद्धविराम खत्म होने का संकेत मिलता है और अगर ये हमले नहीं रुके तो संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे चिंता बढ़ गई कि यह क्षेत्र फिर से युद्ध की चपेट में आ सकता है, जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं और इस होर्मुज से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति रुक सकती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दो दिनों के अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, इनमें से ज्यादातर लोग सशस्त्र बलों के सदस्य थे। कुवैत में सेना ने बताया कि देश द्वारा तीन बैलिस्टिक मिसाइलों, एक क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन को मार गिराने के दौरान मलबे के गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया।

'बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट न करना भी अपराध'

सुप्रीम कोर्ट का प्रधानाध्यापिका को राहत देने से इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा अगर किसी स्कूल में अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण की शिकायत मिलती है तो वह खुद जांच-पड़ताल करके मामले को रफा-दफा नहीं कर सकते। अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 19 के तहत घटना की रिपोर्ट ने करने पर पोक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें छह महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका पर आरोप था कि उन्होंने एक सीनियर छात्र द्वारा आठ साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की शिकायत को दबा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी.विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका को आरोपमुक्त करने का फैसला रद्द कर दिया है।

पीठ ने कहा कि अगर किसी स्कूल अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण की शिकायत मिलती है तो वे खुद जांच-पड़ताल करके नतीजा निकालकर ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी से प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल, शिक्षक और हॉस्टल वार्डन शामिल थे, उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था। पीड़िता ने बताया कि आठवीं कक्षा के एक छात्र ने उसका यौन शोषण किया, जिसकी जानकारी उसने अपनी बहन और स्कूल की प्रधानाध्यापिका को दी थी। पोक्सो एक्ट की धारा 19(1) के तहत प्रधानाध्यापिका ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने की बजाय खुद मामले की जांच-पड़ताल की।

पूछताछ में आरोपी छात्र ने घटना से साफ इनकार किया। जांच में प्रधानाध्यापिका ने नतीजा निकाला कि कुछ नहीं हुआ था और उन्होंने कथित तौर पर घटना को दबा दिया था। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को इस बारे में किसी को भी कुछ न बताने का निर्देश दिया था।

जिस हादसे ने हिला दी थी TVK की नींव, अब CM Vijay बनकर मरहम लगाने लौटे

नई दिल्ली, एजेंसी। विजय के राजनीतिक सफ़र में एक नए नेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक करूर का ज़िला लगभग एक साल तक सबसे मुश्किल दौर रहा है। तमिलनाडु का यही ज़िला, जहाँ विजय के चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, शुक्रवार को फिर से उनका स्वागत कर रहा है; लेकिन इस बार वे वोट माँगने वाले विपक्षी नेता के तौर पर नहीं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। वे उस त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए लौट रहे हैं। सितंबर 2025 में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के प्रमुख विजय की एक चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 110 लोग घायल हो गए। यह हादसा किसी भी राजनीतिक अभियान को खत्म करने के लिए काफी था, खासकर तब जब कोई नया नेता मैदान में हो। इस हादसे में कई कीमती जानें गईं और विजय के देर से पहुंचने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

विदेशी संपत्ति और संदिग्ध लेन-देन, ईडी की कल्याणी इम्पेक्स के ठिकानों पर रेड, कई दस्तावेज जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी संपत्ति और बैंक खातों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने FEMA के तहत कल गुरुवार (9 जुलाई) को कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके एक्टिव डायरेक्टर धर्मेश नरेंद्र सांगानी से जुड़े मामले में छापेमारी की।

जांच के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनमें विदेश में छिपाई गई कई संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय लेन- देन का खुलासा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के प्रावधानों के तहत तलाशी की कार्रवाई की गई।

ईडी की जांच के दौरान यह पता चला कि जो पैसा भारत में आना चाहिए था, वह काफी समय बीतने के बाद भी वापस नहीं आया। कुछ विदेशी खरीदारों से एक्सपोर्ट से मिलने वाली रकम भी नहीं मिली थी और न ही अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने की मंजूरी ली गई। यहां तक की वसूली के लिए किसी तरह की कोई दस्तावेजी कोशिश नहीं की गई।

जांच में यह भी पता चला कि निर्यात का कुछ भुगतान उन विदेशी कंपनियों से लिया गया, जिनका नाम निर्यात दस्तावेजों या शिपिंग बिल में खरीदार के तौर पर दर्ज नहीं था। इससे लेन-देन पर संदेह और गहरा हो गया है।

कनाडा और अमेरिका भी कर रहीं जांच

कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी को बिना बताए विदेशी एसेट्स और विदेशी बैंक अकाउंट से जुड़े होने के सबूत भी मिले। ईडी को छापेमारी के दौरान धर्मेश सांगानी की कनाडा की एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी के सबूत मिले हैं, जिसकी जानकारी संबंधित भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इस कंपनी से जुड़े विदेशी बैंक खाते और लेन-देन भी सामने आए हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक अघोषित कारोबारी इकाई का भी पता चला है। अब तक की जांच में कनाडा, अमेरिका और यूएई में कई अघोषित विदेशी बैंक खातों की पहचान की गई है। ईडी ने यह भी बताया कि धर्मेश सांगानी के कुछ लेन-देन की जांच अमेरिका और ब्रिटेन के सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिकारी भी कर रहे हैं। ईडी इस लेन-देन में FEMA के संभावित उल्लंघन की भी जांच की जा रही है।

टॉक्सिक से जारी हुआ पहला गाना तबाही, कियारा और यश के बीच दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

सिनेप्रेमियों को अगर किसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है तो वह साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड मूवी टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स है। जैसे-जैसे इस बहुचर्चित फिल्म की रिलीज का समय करीब आ रहा है, ठीक वैसे-वैसे मेकर्स की तरफ से इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट दिए जा रहे हैं।

अब टॉक्सिक का पहला गाना तबाही रिलीज किया कर दिया गया है, जिसमें यश और बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के बीच जबरदस्त रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।

टॉक्सिक का सॉन्ग तबाही पहले मेकर्स की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था। इसके फर्स्ट लुक पोस्टर को लेकर भी काफी बवाल मचा था। लेकिन फिल्म की रिलीज डेट बदलने के चलते इसको रिलीज नहीं किया गया था। अब टॉक्सिक का तबाही गाना रिलीज कर दिया गया है, जिसकों हिंदी सहित, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में पेश किया गया है।

फिल्म के इस गीत में अभिनेता यश और अभिनेत्री कियारा आडवाणी इंटीमेट रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गीत को रिलीज करने की जानकारी टॉक्सिक फिल्म के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दी गई है। जिसमें लिखा गया है- सही और गलत के विचारों से परे, एक मैदान है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा- रूमी।

इस तरह से मेकर्स की तरफ से टॉक्सिक का ये फर्स्ट सॉन्ग रिलीज किया गया है। कियारा और यश के अलावा इसमें साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की झलक भी देखने को मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इस मूवी में किसी गैंगस्टर की ग्रुप का हिस्सा बनीं हैं।

तमाम रिलीज डेट बदलने के बाद टॉक्सिक की फाइनल रिलीज डेट सामने आ चुकी है। 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है और इसमें यश, कियारा के अलावा हुम कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

'भय' के दूसरे सीजन पर बड़ा अपडेट, इंडस्ट्री में भेदभाव पर भी बोले करण टैकर, कहा– 'कोई भी बदलाव'

एक्टर करण टैकर हाल ही में शो 'भयः द गौरव तिवारी मिस्ट्री' में नजर आए थे, जिसे दर्शकों से काफी प्यार मिला था। अब एक्टर ने दूसरे सीजन और इंडस्ट्री में भेदभाव को लेकर खुलकर बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। एक्टर करण टैकर ने हाल ही में शो 'भयः द गौरव तिवारी मिस्ट्री' के दूसरे सीजन के बारे में खुलकर बात की और बताया कि अभी उस पर काम चल रहा है।

दूसरे सीजन पर अपडेट देते हुए करण ने कहा, 'मुझे दूसरे सीजन की कुछ सक्रिप्ट पढ़ने के लिए मिली है। अभी उस पर फाइनल काम चल रहा है। उम्मीद है कि साल खत्म होने से पहले इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी।'

करण के लिए शो का दूसरा सीजन मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। वह कहते हैं, 'इस प्रोजेक्ट को लेकर प्लेटफॉर्म के हेड और मेरे अलावा कोई खास एक्साइटेड नहीं था। इसे बनाना काफी मुश्किल था। लेकिन जब किसी शो का दूसरा सीजन आता है, तो यह उसकी सफलता का बड़ा सबूत होता है।'

इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है

करण ने इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस समय एक बड़े बदलाव और गिरावट के दौर से गुजर रही है। आगे क्या करना है, यह तय करना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'अब प्लेटफॉर्म्स भी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम हो रहे हैं। पूरे सिस्टम में एक तरह की समस्या है। कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग कन्फ्यूज हैं और हर कोई फिर से शुरुआत करने की सोच रहा है।'

कंटेंट की भरमार से हो रहा नुकसान

करण का मानना है कि जरूरत से ज्यादा कंटेंट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, 'आजकल इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पीआर के जरिए यह दिखाया जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि असलियत कुछ और है।'

भेदभाव पर क्या बोले करण?

हाल ही में करण सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री में होने वाले भेदभाव को लेकर भी खुलकर बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'यह सब मेरे अपने अनुभव से आता है। जैसे-जैसे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, आपको इसकी कमियां साफ नजर आने लगती हैं। मैं बस वही कह रहा हूं जो सच है।'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन इस सिस्टम में हर कोई बदलाव लाने से डरता है। लोग आपस में सच की बातें कर लेते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से डरते हैं क्योंकि सबको अपनी नौकरी का डर रहता है।'

करण ने आखिर में कहा, 'अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे, तो हालात और खराब होते जाएंगे। आज हम अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी वक्त आ सकता है जब हमारे पास नौकरी ही नहीं होगी।'

दादा से राजकुमार राव की पहली झलक जारी, सौरव गांगुली के अंदाज में आए नजर

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर लंबे समय से चर्चा थी। सौरव गांगुली के 54वें बर्थडे पर उनकी बायोपिक दादाः द सौरव गांगुली स्टोरी का ऑफिशियली एलान हो गया है। साथ ही फिल्म में राजकुमार राव पूर्व कप्तान का रोल करने जा रहे हैं। बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है।

बता दें, फिल्म के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2027 में रिलीज होने जा रही है।

बात करें बायोपिक दादा से आए राजकुमार राव के बतौर सौरव गांगुली लुक की तो बता वह बेहद ही शानदार है। राजकुमार राव बतौर सौरव गांगुली फर्स्ट लुक में लॉर्ड्स के उस पवेलियन में टी-शर्ट उतारकर लहराते दिख रहे हैं, जैसे गांगुली ने 13 जुलाई 2002 को नेट-वेस्ट ट्राई सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद उतारी थी। गांगुली के इस विनिंग गेस्चर पर बहुत बवाल भी हुआ था। टीम इंडिया की इंग्लैंड पर इस ऐतिहासिक जीत की आज भी चर्चा होती है। बता दें, फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी और इसे ईद के मौके पर लंबा हॉलीडे वीकेंड मिलने वाला है।

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक का फर्स्ट लुक शेयर कर अपना रिएक्शन दिया है। दादा ने पोस्टर शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, अब तक का बेस्ट गिफ्ट, मुझे अब अपना कवर ड्राइव शॉर्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा है।

दादाः द सौरव गांगुली स्टोरी का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने ने किया है, इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। गुलशन कुमार, भूषण कुमार, टी-सीरीज़ और डीबीएल ने इसे पेश करने जा रहे हैं। यह फिल्म लव फिल्म्स के बैनर तले बनी है। गौरतलब है कि साल 2021 में सौरव ने अपनी बायोपिक का एलान किया था। बायोपिक में सौरव की शुरुआती जिंदगी से उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने तक की कहानी नजर आएगी। बायोपिक का बजट बड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दादा उर्फ सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना का नाम भी सामने आया था। वहीं, रणबीर के मना करने के बाद आयुष्मान खुराना को रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन एक्टर इस फिल्म से बाहर हो गए। वहीं, बाद में खुद सौरव गांगुली ने राजकुमार राव के नाम पर मुहर लगाई थी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com